CNews सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-198
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर,बुधवार 23 अक्टूबर 2024

आज का विचार

जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते।
- अल्फ्रेड मर्सिएर

लोकसभा के रण में पहली बार प्रियंका गांधी, दाखिल किया नामांकन, रोड-शो में उमड़ी भीड़

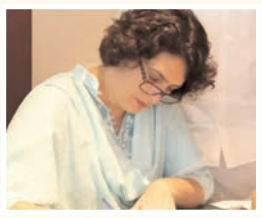

केरला की वायनाड लोकसभा सीट से बुधवार (23 अक्टूबर) को प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रियंका गांधी रोड शो भी करेंगे। प्रियंका की नामांकन रैली में कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मंगलवार (22 अक्टूबर) रात वायनाड पहुंची। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने प्रियंका के खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो भी किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के पित रॉबर्ट वाड्रा और उनके भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस रोड शो के जरिए कांग्रेस ने वायनाड में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। बाद में राहुल गांधी ने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। बता दें कि रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी भी चुनकर लोकसभा पहुंच चुकी हैं। इस बार सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनी हैं।चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर की दोपहर को 13 राज्यों की 47 विधानसभा और लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी। इनमें केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीटें शामिल हैं। अब इस सीट से प्रियंका पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा।महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का एक वीडियो कांग्रेस ने ङ्क पर पोस्ट किया है। प्रियंका के नामांकन दाखिल करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में अलका कह रही हैं कि %लड़की हूं-लड़ सकती हूं% का नारा भारत की राजनीति में बुलंद करने वाली प्रियंका गांधी जी वायनाड में अपना नामांकन भरने जा रही हैं। प्रियंका गांधी जी की आवाज न सिर्फ वायनाड, बल्कि पूरे देश की आधी आबादी के अधिकारों को बुलंद करने का जरिया बनेगी। हम इस मौके पर प्रियंका गांधी जी को अग्रिम जीत की बधाई देते हैं।

शिवसेना के 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी शिंदे कोपड़ी पाचपाखड़ी से लड़ेंगे चुनाव

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति ने अब तक 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें 99 नाम भारतीय जनता पार्टी के और 45 नाम शिवसेना (शिंदे गुट) के हैं। मंगलवार रात शिवसेना (शिंदे गुट) ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कोपड़ी पाचपाखड़ी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट मिला है।

राज ठाकरे के बेटे को सीधी टक्कर देंगे सदानंद- शिवसेना (शिंदे गुट) ने महिम विधानसभा सीट से सदानंद शंकर सरवणकर को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उनका मुकाबला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से होगा। महायुति की इस सूची में शिवसेना के कई दिग्गज नेताओं को मौका दिया गया है। अब तक महायुति ने कुल 144 नामों की घोषणा कर दी है, जिनमें से 99 नाम बीजेपी के और 45 नाम शिवसेना (शिंदे गुट) के हैं।भाजपा ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी की 20 अक्टूबर को भाजपा ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसमें 79 वर्तमान विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। सभी 10 मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी चुनाव में उतारा गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी ष्टरू देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण-पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से उम्मीदवार बनाया गया है।

6 बड़ी पार्टियों के बीच वोट बंटने की चुनौती- महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। महायुति सरकार, जिसमें शिवसेना, भाजपा और एनसीपी (अजीत पवार गुट) शामिल हैं, को इस चुनाव में सत्ता विरोधी लहर और वोट बंटने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। महायुति के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि छह बड़ी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में हैं।

शिंदे के नेतृत्व में पहला चुनाव- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत की थी और भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। यह पहला विधानसभा चुनाव है, जो शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। इस चुनाव में शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा की साझा ताकत को परखा जाएगा।

दो भाइयों की चुनावी लड़ाई- मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से और उनके भाई किरण सामंत को राजापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, स्वर्गीय शिवसेना विधायक अनिल बाबर के बेटे सुहास बाबर को खानापुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। यह चुनाव न केवल महायुति के लिए बल्कि कई राजनीतिक परिवारों के लिए भी अहम साबित होगा।

ओडिशा और बंगाल में अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद, 198 ट्रेनें रद्द, 10 लाख लोग सुरक्षित स्थान पर भेजे गए

ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने 25 अक्टूबर को आने वाले तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस तूफान के कारण हवाएं 100 से 120 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसके चलते दोनों राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। ओडिशा के 14 जिलों जैसे पुरी, कटक, बालासोर और गंजाम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने 10 लाख से अधिक लोगों को 3,000 से ज्यादा गांवों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने राज्य में तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में विशेष राहत कैंप स्थापित किए हैं, जहां पानी, भोजन और दवाओं का इंतजाम किया गया है। इन तैयारियों के बीच, स्थानीय प्रशासन भी लगातार सतर्क है।

198 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं तूफान के मद्देनजर ओडिशा से गुजरने वाली 198 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें प्रमुख ट्रेनें जैसे तिरुनेलवेली से शालीमार स्पेशल और भुवनेश्वर से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अनावश्यक यात्रा से बचने का अनुरोध किया है। ट्रेन सेवाएं प्रभावित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो त्योहारों के दौरान यात्रा की योजना बना रहे थे।

दो राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद -तूफान के चलते ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ओडिशा सरकार ने 14 जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक सभी शैक्षिक संस्थान बंद रखने के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में भी सात जिलों में स्कूल बंद रहेंगे।

पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

प्रमुख निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा विंध्य...

भोपाल। मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए बुधवार को रीवा में 'वाइब्रेंट विंध्य'नामक पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को एक प्रमुख निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस आयोजन को प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2025 को 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' घोषित किया है, जिससे रोजगार और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाले इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3000 से अधिक एमएसएमई उद्यमी शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव का फोकस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्र-संस्करण, पर्यटन और हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस पहल से निवेशकों और उद्यमियों के बीच संवाद को सशक्त बनाने और राज्य में औद्योगिक विकास के नए द्वार खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के कई विभाग, जैसे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, आईटी, खनन, ऊर्जा और पर्यटन विभाग प्रमुख प्रस्तुतियां देंगे। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंडटेबल सत्र का आयोजन होगा, जिसमें उभरते उद्योगों के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा चार सेक्टोरल-सत्र भी आयोजित होंगे, जो एमएसएमई, स्टार्टअप्स, खनन, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में निवेश के अवसरों पर केंद्रित होंगे। कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 20 से अधिक प्रमुख निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठक करेंगे, जिससे निवेश और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रीवा आईटी पार्क और चुरहटा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमिपूजन करेंगे। इसके साथ ही, 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि रीवा में खनिज, फूड पार्क सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। बुधवार को फार्मा सेक्टर पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। यहां रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि आ रहे हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद पश्चाताप

देश विरोधी नारे लगाने वाले फैजल ने दी तिरंगे को 21 बार सलामी

भोपाल। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मध्यप्रदेश के युवक फैजल ने मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर तिरंगे को 21 बार सलामी दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैजल ने भोपाल के थाने में 21 बार 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। उसने पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारा लगाने पर पश्चाताप भी जाहिर किया। उसने कहा कि रील बनाते हुए उसने गलती से वह नारा लगा दिया था। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने फैजल को जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि उसे महीने में दो बार भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे को सलामी देनी होगी। मामले का निपटारा होने तक उसे महीने के हर पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देने के साथ भारत माता की जय का नारा लगाना है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैजल ने इसकी शुरुआत कर दी है। जस्टिस डीके पालीवाल ने 15 अक्टूबर को आदेश में कहा था कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिससे उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जहां वह पैदा हुआ और रह रहा है। अदालत ने कहा था कि वह खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है। आरोपी फैजल उर्फ फैजान को मई में भोपाल के मिसरोद थाने में आईपीसी की धारा 153बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उसकी करतूत विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के समान है और सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि उसके मुवक्किल को झूठे आरोप में फंसाया गया है। राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दिसंबर तक एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी एमपी सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में विभिन्न विभागों के खाली पड़े एक लाख सरकारी पदों पर जल्द भर्ती करने का निर्णय लिया गया। बैठक में दिसंबर 2024 तक एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के 6388 नवीन पद (5936 नियमित एवं 452 संविदा) शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रोजगार सृजन पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिए कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें। रोजगार सृजन के लिए 11 विभाग काम कर रहे हैं। अगले चार साल के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कितने रोजगार के अवसर तैयार किए जा सकते हैं, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध कराने के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं। कैबिनेट में मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 12 हजार 670 सहायिका और 470 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किए गए है। इस पर 213 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार और 34 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। कैबिनेट में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन मिलेगी। इसका लाभ 2016 से जो सेवानिवृत्त हुए है, उनको मिलेगा। उज्जैन में सिंहस्थ के

लिए हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। हालांकि, इस जमीन का अखाड़े आवासीय और कमर्शियल उपयोग नहीं कर सकेंगे। दीपावली को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन मिलेगा। इसके साथ ही दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर राज्य की शासकीय और अनुदान प्राप्त गौशालाओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने गृह जिलों की गौशालाओं में गोवर्धन पूजा पर शामिल होने को कहा है।

प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को मंजूरी- कैबिनेट ने प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत आम नागरिक और जनप्रतिनिधि पुनर्गठन आयोग को अपने सुझाव दे सकेंगे। पुनर्गठन आयोग विभिन्न संभागों का दौरा नवंबर से शुरू करेगा और इसके लिए लोगों को अपने आवेदन और सुझाव देने के लिए चार से छह महीने का समय मिलेगा। फीडबैक के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सरकार की मंजूरी मिलने पर उसे लागू किया जाएगा।

25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी सोयाबीन खरीदी- कृषि क्षेत्र में राहत के तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि 25 अक्टूबर से मध्यप्रदेश में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो जाएगी। इस वर्ष 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है और राज्य सरकार किसानों से 4892 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन खरीदेगी। इसके लिए राज्य में 1400 से अधिक उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

यौन शोषण की शिकार बच्चियों को आर्थिक सहायता देगी सरकार कैबिनेट बैठक में यौन शोषण की शिकार होने वाली बच्चियों को आर्थिक सहायता का भी फैसला किया गया। कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया है। योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक के लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फंड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। पीड़ितों को सहायता के लिए जिले आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ित नाबालिग गर्भवती बालिका को पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीड़िता को तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना एवं दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए विभिन्न सुविधाएं जैसे शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा जिसमें मातृत्व, नवजात शिशु, शिशु की देख-भाल शामिल है। साथ ही मनोवैज्ञानिक, कानूनी सहायता आदि सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। मंत्री ने बताया कि यह योजना महिला-बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्भया फंड के तहत 100 प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित योजना के रूप में संचालित की जायेगी। इसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए आवंटित किये जायेंगे। राज्य वास्तविक घटना और जिलों की आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकते हैं। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी इस निधि का उपयोग जिला कलेक्टर के समग्र नियंत्रण में कर सकेंगे।

सिंगल कॉलम

छत्रीपुरा इलाके में गोली चलाने वाले दो युवक गिरफ्तार...

इंदौर। इंदौर के छत्रीपुरा इलाके में सोमवार देर रात हुई गोली चलने की घटना के मामले में पुलिस ने मंगलवार को दो युवकों को हिरासत में लिया है। ये दोनों युवक दोस्त हैं और मस्ती-मजाक में पिस्टल चलाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। घटना का खुलासा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से किया है। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि छत्रीपुरा के राज मोहल्ले में रात को गोली चलने की सूचना मिली थी लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था, केवल सड़क पर थोड़ा खून नजर आया था, जिससे पहले एक्सीडेंट का संदेह हुआ। बाद में जांच में पाया गया कि शाहरुख नामक युवक ने भूपेंद्र की पिस्टल ली थी और लोड करके टेस्ट कर रहा था, उसी समय गलती से गोली चल गई और शाहरुख गिर पड़ा। इसके बाद एक और फायर हुआ और दोनों आरोपी घबरा कर भाग गए। इस मामले में दोनों के खिलाफ धारा 336 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुछ देर पहले ही पूर्व मंत्री उषा ठाकुर वहां से निकली थी। जहां गोली चली उसके पास वाले घर में वे अपनी मित्र से मिलने के लिए आईं थी। उनके निकलते ही गोली चलने पर सनसनी फैल गई। दोनों दोस्त हैं। एक दोस्त ने पिस्टल चलाने लिये पूछा और मस्ती - मजाक में गोली चल गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने शाहरुख निवासी पढ़रीनाथ और भूपेंद्र जोशी निवासी रामबाग को हिरासत में लिया है। पिस्टल भूपेंद्र की थी। शाहरुख ने टेस्ट करने के लिए भूपेंद्र से पिस्टल लोड करवाई। इस बीच गोली चल गई और शाहरुख हडबडाहट में गाड़ी से गिर गया। इसी दौरान भूपेंद्र से दूसरा फायर हो गया। इसके बाद दोनो घबराकर मौके से भाग निकले। डीसीपी के मुताबिक, 336 और 25 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं।

इंदौर देवास रोड पर घंटों रेंगते रहे वाहन, देवास नाका से मांगलिया तक लगा जाम

इंदौर। इंदौर शहर में आए दिन यातायात उलझने की समस्या बढ़ती जा रही है। यहां कब किस वजह से और कहां ट्रैफिक फंस जाए कुछ कह नहीं सकते। मंगलवार को एक बार फिर मांगलिया से देवास नाका के बीच सुबह जाम लग गया। जिससे हजारों की संख्या में वाहन घंटों रेंगते हुए नजर आए। दरअसल पंचवटी के पास एक ट्रक सड़क पर फंसने के कारण दोनों लेन पर जाम लग गया। सुबह करीब 10 बजे लगा जाम दोपहर तक बड़ी मुश्किल से खुल पाया। देवास नाका से मांगलिया के बीच दर्जनों टाउनशिप बन गई है, जिनमें हजारों लोग निवास करते हैं। हर दिन सुबह बड़ी संख्या में वाहन चालक नौकरी आदि के लिए शहर में आते हैं। डिवाइडर के बीच बने कट बन रहे जाम लगने का कारण इधर इस रोड पर भारी वाहन सड़क पर ही पार्क रहते हैं। इसके साथ ही डिवाइडर के बीच बने कट पर भी भारी वाहनों को लंबा टर्न लेना होता है, जिससे कई अन्य वाहन फंस जाते हैं और थोड़ी देर में ही जाम लग जाता है। मंगलवार को भी पंचवटी के पास एक ट्रक फंस गया। जिसके बाद दोनों लेन पर जाम लगने लगा। देखते ही देखते यह जाम दो से तीन किमी लंबा हो गया। इस दौरान वाहन रेंगते हुए ही आगे बढ़ते रहे। इस दौरान नौकरीपेशा वाहन चालक काफी परेशान होते रहे।

ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क के नाम पर 60 लाख की ठग

इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर की शिकायत पर फ्रॉड का केस दर्ज किया है। केस दो मोबाइल नंबर के यूजर्स पर किया गया। आरोपियों ने गोल्ड कंपनी में ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क का झांसा देकर हर दिन 4 हजार रुपए तक कमाने का लालच दिया। उनसे करीब 60 लाख रुपए की ठगी कर दी।क्राइम ब्रांच ने मोहम्मद हिदायतुल्ला खान की शिकायत पर सौम्या प्रकाश और एक अन्य आरोपी पर केस दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कई ट्रांजेक्शन के जरिए 59 लाख 94 हजार की धोखाधड़ी की है।हिदायतुल्ला के मुताबिक, वे पीथमपुर में निजी कंपनी में काम करते हैं। उनके पास वॉट्सऐप नंबर से मैसेज आया। मैसेज भेजने वाली लड़की ने अपना नाम सौम्या प्रकाश बताया। उसने पार्ट टाइम काम का आफर दिया। हर दिन 2 से 4 हजार रुपए इनकम की बात कही। शुरू में तो इनकार किया, लेकिन लड़की ने डेमो देने की बात कही। इस पर उसकी बात मान ली। हिदायतुल्ला ने बताया कि अपना नाम सौम्या बताने वाली लड़की ने उन्हें पोर्टल लिंक भेजी। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने का कहा। बोली कि उसकी गोल्ड कंपनी अकाउंट में 10 हजार रुपए डाल देगी। 18 टास्क पूरे करने होंगे। गोल्ड की ज्वेलरी दिखाना होगी। सेल आईकॉन का बटन दबाने पर वह बिक जाएगी। प्रत्येक ज्वेलरी की कीमत और ब्रिकी मूल्य अलग होगा। इसके बदले कमिशन मिलेगा। 25 अगस्त को उन्होंने 1125 रुपए का प्रॉफिट दिया। इसके बाद आरोपियों की ओर से तीन लिंक दी गईं।

'आग के गोदाम' पर बैठा था इंदौर

चंदननगर में मिला 11 हजार लीटर 'पेट्रोलियम', अफसरों का छूटा पसीना

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में दिवाली से पहले मंगलवार को जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल विभाग ने एक ही जगह से करीब 11 हजार लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब्त किए। यहां इंडस्ट्रीयल तेल के बिल बनाकर ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद बेचे जा रहे थे। इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ देखकर अफसरों का पसीना छूट गया। यह कार्रवाई जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए ज्वलनशील अवैध पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण, क्रय-विक्रय के तहत की गई। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि मंगलवार को खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा प्राप्त सूचना पर स्कीम नंबर 71, मेकेनिक नगर चंदन नगर इंदौर स्थित फर्म मार्क इंटरप्रायजेस पर औचक निरीक्षण किया गया। फर्म के गोदाम में मौके पर भारी मात्रा में दो-दो सौ लीटर के 56 ड्रम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भरे हुए मिले। साथ ही 400 से ज्यादा खाली ड्रम भी पाए गए। गोदाम परिसर में पाए गए

प्रोडक्ट के प्रारंभिक जांच में अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलीय पदार्थ पाया गया। विक्रय के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले मार्क इंटरप्रायजेस का मालिक अंकित बाफना है। बाफना द्वारा अलाईस कार्पोरेशन गुजरात से इंडस्ट्रीयल फ्यूल आइल के नाम से बिल प्रस्तुत किया गया, किन्तु प्रोडक्ट विक्रय के बिल और विक्रय के कोई वैध दस्तावेज जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। इंडस्ट्रीयल फ्यूल आइल का नाम, कंटेंट, लैबोटरी आदि के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इंडस्टी:यल ऑयल केवल इंडस्ट्री उपयोग के लिए होता है लेकिन मौके पर किसी प्रकार की फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं पाई गई। प्रारंभिक जांच में इंडस्ट्रीयल फ्यूल आइल के तथाकथित बिल की आड़ में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भंडारण, क्रय विक्रय करना पाया गया, जिसके लिए विस्फोटक विभाग एवं कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी कोई वैध अनुमति लायसेंस नहीं पाए गए तथा मौके पर आगजनी की सुरक्षा के लिए फायर फायटर आदि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं पाए गए। जांच दल द्वारा प्रोडक्ट कपड़े पर डालकर जलाने पर अत्यंत ज्वलनशील होना पाया गया।

केवल इंडस्ट्री में हो सकता है इस्तेमाल

यह इंडस्ट्रीयल तेल केवल इंडस्ट्री में उपयोग होता है और उसी परिसर में आता है।

जहां इंडस्ट्री का कोई पदार्थ बन रहा हो। मौके पर टीम ने पाया कि ट्रेडिंग का भंडारण केंद्र बना रखा है, जबकि इंडस्ट्रीयल तेल वर्जित तेल है। जिसकी ट्रेडिंग या खैरची में बिक्री नहीं कर सकते, केवल इंडस्ट्री में ही उपयोग कर सकते हैं। इंडस्ट्रीयल तेल के फर्जी बिल बनाकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे, जिसके लिए लाइसेंस और विस्फोटक अनुमति आवश्यक है। यहां अवैध व्यापार व भंडारण भी किया जा रहा था। साथ ही कलेक्टर से लाइसेंस विस्फोटक अनुमति आवश्यक होती है।

अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलीय पदार्थ पाए जाने पर मौके से विधिवत पेट्रोलियम पदार्थ की सैंपलिंग कर 56 भरे ड्रम (लगभग मात्रा-11200 लीटर) जप्त कर सुरक्षित जगह सुपुर्दगी में दिए गए। गोदाम में क्रय-विक्रय,भंडार में उपयोग किए जाने वाले बैरल जप्त कर फर्म के गोदाम परिसर को सील किया गया। सैंपल जांच हेतु आइल कंपनी की अधिकृत प्रयोगशाला में भेजने की कार्यवाही की जा रही है। अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलीय पदार्थ का अवैध क्रय-विक्रय भंडारण करने पर मार्क इंटरप्रायजेस एवं अन्य के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में उक्त प्रोडक्ट किन-किन को विक्रय किया गया तथा उपयोग किया गया, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। जांच कार्यवाही में जिला आपूर्ति नियंत्रक एम. एल. मारू, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दिलीप मनवारे, शिवसुंदर व्यास, राहुल शर्मा, सौरभ यादव आदि शामिल थे।

इंदौर के नाम एक और उपलब्धि दर्ज मिला बेस्ट वाटर डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। पांचवें नेशनल वाटर अवॉर्ड में इंदौर जिला वेस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक कैटेगरी में नंबर वन आया है। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त शिवम वर्मा को अवॉर्ड से सम्मानित किया। नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग ने मंगलवार को अलग-अलग श्रेणियों में 30 से ज्यादा अवॉर्ड बांटे। देश के अलग अलग प्रदेशों, निकायों, जिले व अन्य श्रेणियों में अवॉर्ड दिए गए। इंदौर जिले के लिए जिला पंचायत की तरफ से जलसंवर्धन, जल पुनर्भरण और नदियों के कैचमेंट एरिया के लिए किए गए कामों के आधार पर प्रविष्ठी भेजी गई थी। विभाग ने इंदौर जिले के कामों को पश्चिम जोन में सबसे बेहतर पाया और पुरस्कार के लिए चुना। इंदौर को दस में से दस अंक दिए गए। जल सरंक्षण के लिए किए गए कामों को परखने के लिए दिल्ली से जो टीम आई थी। उन्हें गर्मी के समय भी बोरिंग सूखे नहीं दिखे और नदियों में भरपूर पानी मिला। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जनभागीदारी से यह काम संभव हो पाया है। जलसरंक्षण की दिशा में लगातार इंदौर जिले में काम जारी रहेंगे।

9 श्रेणियों में दिए गए अवॉर्ड

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2023 में 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित 38 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान (स्कूल या कॉलेज के अलावा) और

सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज शामिल हैं।

जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने बताया कि अवॉर्ड के लिए जिला पंचायत की ओर से नॉमिनेशन किया गया था। हमने जिले की नदियों के कैचमेंट एरिया में जल संवर्धन ट्रीटमेंट के लिए प्लानिंग की थी। ग्राम पंचायत वार जीआईएस आधारित योजना तैयार बनाई गई। इससे कनाड, कारम, अजनार, चोरल, बालम नदियों के जल प्रवाह और संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। इंदौर को 10 में से 10 अंक मिले थे। मई 2024 में इसके लिए जो टीम आई थी, उसने ग्राम मलेंडी, बड़िया, बुरालिया, जाम बुजुर्ग में गर्मी के दिनों में भी नदियों में बहता पानी देखा था।

कलेक्टर ने इंदौर को कहा धन्यवाद

मंगलवार रात को कलेक्टर, निगम कमिश्नर अवॉर्ड लेकर दिल्ली से इंदौर लौटे। कलेक्टर कहा कि यह इंदौर की जनता के प्रयास से संभव हुआ है। उन्होंने इंदौर की जनता, जनप्रतिनिधियों, मीडिया को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर में जल संरक्षण को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, वे फलीभूत होते जा रहे हैं। इसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र में काफी अच्छे काम हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की कई नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। कई माध्यमों से जल संरक्षण किया जा रहा है।

नदियों पर छोटे-छोटे स्टॉप डेम बनाए गए इंदौर से निकलने वाली नदियों पर छोटे-छोटे स्टॉप डेम बनाए गए। इससे नदियों में वर्षभर पानी रहता है और किसान भी उससे खेतों की सिंचाई करते हैं। इसके अलावा इंदौर में 300 से ज्यादा हेक्टेयर में ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया। नगर निगम सीमा क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा आवासों में छत से सीधे जमीन में पानी उतारा जाता है। जिले के अमृत सरोवरों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। उनकी चैनलों को साफ किया गया। मेंहदी कुंड, पातालापानी झरनों की अप स्ट्रीप में वाटरशेण का विकास किया गया। झरने वषार्काल के बाद भी बहते रहे, इसके लिए प्रबंध किए गए।

मुख्यमंत्री ने दी इंदौर को दी बधाई

इंदौर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के तौर पर मिले अवार्ड के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश जल सरंक्षण के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। इंदौर में नदिया जोड़ने की दिशा में भी बेहतर काम हुए है।

आईडीए छोड़ेगा स्कीम नंबर 171, तीस सालों से अटके थे

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण ने योजना क्रमांक 171 छोड़ने की तैयारी कर ली है।इससे सैकड़ों भूखंडधारियों को राहत मिलेगी।इस स्कीम को डीनोटिफिकेशन करने के प्रस्ताव को सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी आर पी अहिरवार ने बताया कि योजना क्रमांक 171 का धारा 50 (7)में 12 साल पहले प्रकाशन हुआ था। योजना का कुल रकबा 151.553 हेक्टेयर है। योजना में वर्तमान में एक हजार से अधिक मकान निर्मित है और इसके भू धारकों की संख्या 221 है। मकानों की खरीदी बिक्री नहीं हो पाती थी। तेरह गृह निर्माण संस्थाओं की भूमि इस योजना में शामिल है, प्राधिकरण ने इस योजना में लगभग छह करोड़ विभिन्न कामों में खर्च किए। स्कीम छोड़ने के एवज में राज्य शासन इसकी वसूली की गणना कर इसकी राशि भू धारकों से वसूल करेगी। पांच रुपए प्रति स्क्वायर फीट की राशि भू धारकों से वसूल कर आईडीए योजना को डी नोटिफाई कर सकेगा। इससे कई परिवारों को उनके प्लाटों पर मकान बनाने की राह आसान होगी, क्योंकि स्कीम के कारण नक्शे पास नहीं होते थे,क्योंकि प्राधिकरण की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। 30 साल पहले यह स्कीम 132 कहलाती थी। वर्ष 2012 में हाईकोर्ट ने इस स्कीम को खारिज कर दिया था। प्राधिकरण ने फिर इसे 171 क्रमांक से लागू कर दिया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए संशोधन के बाद प्राधिकरण ने उन जमीनों को छोड़ने का फैसला लिय था। जहां 10 प्रतिशत से कम विकास कार्य किए गए और स्कीम को लागू करने में लंबा वक्त हो चुका है। इस स्कीम को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका लगी थी। तब प्राधिकरण ने इसे लैप्स करने की बात कही थी। बाद में शासन से प्राधिकरण ने अभिमत मांगा था।

आपको बता दे कि इस स्कीम में देवी अहिल्या गृह निर्माण संस्था, न्याय विभाग, इंदौर विकास गृह निर्माण संस्था, मजदूर पंचायत, अप्सरा गृह निर्माण संस्था सहित तेरह संस्थाएं है। कुछ संस्थाए भूमाफिया के चुंगल में है और सदस्यों के प्लॉट गलत तरीके बेच दिए गए। अब प्राधिकरण के समक्ष असली प्लॉटधारकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देना भी मुश्किल होगा,क्योकि सहकारिता विभाग की वरीयता सूची को लेकर भी विवाद होता है।

भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष और पत्नी पर 420 का केस

इंदौर। इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने एक व्यापारी की शिकायत पर बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कपिल गोयल और उसकी पत्नी दीपिका के खिलाफ 420,406,34 धारा में केस दर्ज किया है। व्यापारी ने अप्रैल 2024 में उपाध्यक्ष के खिलाफ कमिश्नर को लिखित शिकायत की थी। मामले की जांच एसीपी को सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दोनों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि युवा मोर्चा अध्यक्ष सौगात मिश्रा और उपाध्यक्ष कपिल गोयल के खिलाफ दो करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। इस लेनदेन की पहली बातचीत पार्टी कार्यालय पर ही हुई थी। फरियादी व्यापारी भाजपा से जुड़ा है। इसका जिक्र भी उसने शिकायत में किया था। शिकायत की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत पार्टी के बड़े नेताओं और पुलिस कमिश्नर को भेजी थी। एमजी रोड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार व्यापार का नाम जयेश पुत्र लक्ष्मी नारायण व्यास, निवासी नारायण बाग कॉलोनी है। जयेश ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे के माध्यम से बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कपिल गोयल और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। जयेश ने अपनी शिकायत में बताया था कि बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा के माध्यम से उनकी पहचान कपिल गोयल से हुई थी। कपिल ने बताया था कि उसे एक प्रॉपर्टी का सौदा करना है। इसके लिये दो करोड़ की मांग की थी।

बंगाली कॉलोनी-बिचौली हप्सी मार्ग पर 50 से ज्यादा दुकानों से अतिक्रमण हटाए

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। दीपावली त्योहार आते ही इंदौर के कई प्रमुख मार्गों पर दुकानदार फुटपाथ और आधी सड़कों पर सामान सजा देते है और ट्रैफिक की बैंड बज जाती है। अब प्रशासन और नगर निगम ने मिलकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम छेड़ दी है। मंगलवार को 50 से ज्यादा दुकानों से अतिक्रमण हटाए गए। लोगों ने शेड लगाकर फुटपाथ और सड़क घेर ली थी। नगर निगम ने तीन ट्रक सामान जब्त किया। इस मुहिम का व्यापारियों ने

विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल मौजूद रहने के कारण मुहिम प्रभावित नहीं हुई। दुकानदारों के चालान बनाकर 50 हजार रुपये वसूले गए। दो दुकानें पार्किंग के लिए बने बेसमेंट में संचालित हो रही थी। उन्हें भी अफसरों ने सील कर दिया। इसी मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर खड़े वाहनों के चालान बनाए। दस वाहनों को जब्त कर ट्रैफिक थाने पहुंचाया गया। एक बस भी सड़क पर जगह घेरकर खड़ी थी। उसका भी चालान काटा गया। इस मुहिम में आईएएस रोहित सिसौनिया, ज्योति शर्मा, ट्रैफिक के एडिशनल डीसीपी अरविंद तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। शहर के अन्य व्यस्त मार्गों पर भी इस तरह की मुहिम चलेगी।

दिवाली से नौ दिन पहले जमकर बारिश... तेज हवा ने कंपकंपाया

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में मंगलवार शाम को अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। दिनभर तेज धूप के बाद शाम होते-होते मौसम ने करवट ली। शाम 4 बजे तक आसमान साफ था और धूप खिली हुई थी, लेकिन उसके बाद बादल छाने लगे। कुछ ही समय बाद तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे लोगों को मौसम में बदलाव का एहसास हुआ। शाम 6 बजे के आसपास कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हुई और धीरे-धीरे यह बूंदाबांदी तेज बारिश में बदल गई। करीब आधे घंटे तक हुई इस तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरने लगा और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। बारिश से पहले शाम 5.30 बजे तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम में ठंडक घुल गई। इस अचानक बदले मौसम ने न सिर्फ लोगों को हैरान किया, बल्कि ठंड के आगमन का भी संकेत दिया। मौसम विभाग के अनुसार, इस बारिश का कारण लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सकुर्लेशन सिस्टम है, जो वर्तमान में सक्रिय है। इस सिस्टम के कारण हवा के दबाव में बदलाव हो रहा है और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है।

तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुली छोड़ रखी थीं, लेकिन अचानक आई बारिश ने उन्हें जल्दी से सामान समेटने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा, जो लोग खरीदारी या अन्य कामों के लिए घर से बाहर निकले थे, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बारिश के कारण सड़क पर फिसलन और जलभराव से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, जिससे लोग देर तक जाम में फंसे रहे। धीरे-धीरे ठंड का असर बढ़ेगा मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे-धीरे ठंड का असर बढ़ेगा। पिछले 10 साल के ट्रेंड को देखें तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रात का तापमान तेजी से गिरने लगता है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस साल भी ठंड जल्दी आएगी और रात के समय तापमान में तेजी से गिरावट देखी जाएगी। मध्यप्रदेश से 15 अक्टूबर को मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी है, लेकिन सिस्टम की सक्रियता के कारण प्रदेश के कई जिलों में अभी भी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, बैतूल, मुरैना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला और बालाघाट जैसे जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है।

मौसम के बदलाव सामान्य

मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अक्टूबर के अंत में मौसम में इस तरह के बदलाव सामान्य माने जाते हैं। ठंड का असर अब प्रदेश में दिखाई देने लगेगा, और जैसे-जैसे समय बीतेगा, ठंडक बढ़ेगी। इस मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण वातावरण में बने दबाव के क्षेत्र और चक्रवातीय गतिविधियां हैं, जो अप्रत्याशित बारिश और हवाओं को जन्म दे रही हैं। इस प्रकार, इंदौर और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में अचानक मौसम के बदलाव ने ठंड के आगमन का संकेत दिया है, जो आने वाले दिनों में और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होगा।

केंद्र सरकार को जल्द ही भेजा जाएगा प्रस्ताव

मप्र में चीतों के बाद अब किंग कोबरा को बसाने की तैयारी

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश जल्द ही अपने जंगलों में किंग कोबरा को फिर से बसाने की योजना बना रहा है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अगर मंजूरी मिल जाती है, तो यह प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश में चीतों के सफल पुनर्वास के बाद एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। एमपी वन विभाग किंग कोबरा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह विशाल सांप, जो 18 से 20 फीट (5 से 6 मीटर) तक लंबा हो सकता है, को भारत का आधिकारिक सरीसृप माना जाता है। यह मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पाया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि किंग कोबरा वर्तमान में एमपी में मौजूद हैं या नहीं। एपीसीसीएफ एल कृष्णमूर्ति के अनुसार एमपी में कोबरा सांप पाया जाता है, लेकिन वर्तमान में एमपी में किंग कोबरा की मौजूदगी के कोई प्रमाण फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सांपों की गणना नहीं की जाती है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि वे कहां और कितनी संख्या में हैं।

महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है किंग कोबरा

किंग कोबरा पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं, इसलिए यह संभावना है कि वे एमपी के जंगलों में भी रहते हों। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य में किंग कोबरा की आबादी को फिर से स्थापित करना है, जो पहले यहां पाए जाते थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में पूर्वी और पश्चिमी घाट क्षेत्र में भी उसकी उपस्थिति मिलती है। पूर्वी घाट में तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, दक्षिणी पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में यह मिलता है। वहीं पश्चिमी घाट क्षेत्र में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाए जाते हैं। ग्रेट अंडमान श्रृंखला के बाराटांग द्वीप पर पर किंग कोबरा मिलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मप्र से सटे हुए राज्य हैं, इसलिए नजदीकी जलवायु होने के कारण यहां के किंग कोबरा मप्र लाने की अधिक संभावना है।

अन्य सांपों का शिकार करता है किंग कोबरा

किंग कोबरा को 'नागराज' भी कहा जाता है, जो अन्य सांपों का शिकार करता है। यह एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने अंडे देने के लिए पेड़ों पर घोंसला बनाता है। इसे भारत के कई हिस्सों में भगवान शिव के गले में लिपटे नाग के रूप में पूजा जाता है। हालांकि, किंग कोबरा एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इसके बावजूद, यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी आबादी को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही किंग कोबरा के संरक्षण के लिए जन जागरूकता पैदा करना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए कदम उठाना भी महत्वपूर्ण होगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुआ है प्रोजेक्ट

यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर शुरू किया गया है, जिन्होंने राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में किंग कोबरा सहित उन सभी जानवरों को वापस लाने के निर्देश दिए थे। यह कभी एमपी में रहते थे, लेकिन अब विलुप्त हो चुके हैं। ये घने वन के अलावा खुले जंगल, बांस के घने जंगल और नदियों के पास रहना पसंद करते हैं। गौरतलब है कि दुनियाभर में सांपों की 3600 प्रजातियां हैं। भारत में सांपों 333 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से किंग कोबरा सांप की प्रजाति मध्य प्रदेश में धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इसकी बड़ी वजह सांप पकड़ने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा होना बताया जा रहा है। उन्हें अनुमति नहीं है, फिर भी वे सांप पकड़ते हैं। अधिकांश प्रकरणों में तो सांपों की तस्करी की भी बातें सामने आ चुकी हैं। वन विभाग के अधिकारियों की मानें तो मध्य प्रदेश में कोबरा और रसेल वाइपर की प्रजाति खत्म होती जा रही है।

दिवाली और छठ पर भोपाल मंडल से गुजरेंगी आठ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा इस वर्ष 6000 से अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये विशेष ट्रेनें 30 नवंबर तक चलाई जा रही है। हर वर्ष की तरह, इस बार भी त्योहारों के दौरान भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की गई है। विशेष रूप से, भोपाल मंडल से 8 विशेष ट्रेनें गुजरेंगी, जो यात्रियों को राहत प्रदान करेंगी। त्योहारों के समय, विशेषकर दिवाली और छठ पूजा के दौरान, उत्तरप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की ओर बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। रेलवे की इस पहल से यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव होगा और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस बार रेलवे ने त्योहारों के दौरान भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है, जिससे लोगों को समय पर यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

भोपाल मंडल से गुजरने वाली 8 विशेष ट्रेन

1- एलटीटी-दानापुर दैनिक विशेष

- 01143ञ एलटीटी मुंबई से प्रस्थान रोजाना 10ञ30 बजे (22.10.2024 से 11.11.2024), दानापुर पहुंचने का समय अगले दिन 18ञ45 बजे।

- 01144ञ दानापुर से प्रस्थान रोजाना 21ञ30 बजे (23.10.2024 से 12.11.2024), एलटीटी मुंबई पहुंचने का समय तीसरे दिन 04ञ50 बजे।

- ठहरावञ ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा।

2- सीएसएमटी-आसनसोल साप्ताहिक विशेष

- 01145ञ सीएसएमटी मुंबई से प्रस्थान हर सोमवार 11ञ05 बजे (21.10.2024 से 11.11.2024), आसनसोल पहुंचने का समय तीसरे दिन 02ञ30 बजे।

- 01146ञ आसनसोल से प्रस्थान हर बुधवार 21ञ00 बजे (23.10.2024 से 13.11.2024), सीएसएमटी मुंबई पहुंचने का समय तीसरे दिन 08ञ15 बजे।

-ठहरावञ दादर, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी, सासाराम, गया, धनबाद।

3- पुणे-दानापुर दैनिक विशेष

-01205ञ पुणे से प्रस्थान रोजाना 15ञ30 बजे (25.10.2024 से 07.11.2024), दानापुर पहुंचने का समय अगले दिन 02ञ00 बजे।

-01206ञ दानापुर से प्रस्थान रोजाना 05ञ30 बजे (27.10.2024 से 09.11.2024), पुणे पहुंचने का समय अगले दिन 18ञ15 बजे।

-ठहरावञ दौंड, अहमदनगर, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं.।

4- सीएसएमटी-अगरतला साप्ताहिक विशेष

-01065ञ सीएसएमटी मुंबई से प्रस्थान प्रत्येक गुरुवार 11ञ05 बजे (31.10.2024 और 07.11.2024), अगरतला पहुंचने का समय रविवार 01ञ10 बजे।

-01066ञ अगरतला से प्रस्थान प्रत्येक रविवार 15ञ10 बजे (03.11.2024 और 10.11.2024), सीएसएमटी मुंबई पहुंचने का समय बुधवार 03ञ50 बजे।

-ठहरावञ दादर, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी और अन्य।

5- एलटीटी-मुंबई बनारस साप्ताहिक विशेष

-01053ञ एलटीटी मुंबई से प्रस्थान प्रत्येक बुधवार 12ञ15 बजे (30.10.2024 और 06.11.2024), बनारस पहुंचने का समय अगले दिन 16ञ05 बजे।

-01054ञ बनारस से प्रस्थान प्रत्येक गुरुवार 20ञ30 बजे (31.10.2024 और 07.11.2024), एलटीटी मुंबई पहुंचने का समय अगले दिन 23ञ55 बजे।

-ठहरावञ कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी, वाराणसी।

6- एलटीटी-दानापुर द्वि-साप्ताहिक विशेष

-01009ञ एलटीटी मुंबई से प्रस्थान हर सोमवार और शनिवार 12ञ15 बजे (26.10.2024, 28.10.2024, 02.11.2024 और 04.11.2024), दानापुर पहुंचने का समय अगले दिन 17ञ00 बजे।

-01010ञ दानापुर से प्रस्थान प्रत्येक मंगलवार और रविवार 18ञ15 बजे (27.10.2024, 29.10.2024, 03.11.2024 और 05.11.2024), एलटीटी मुंबई पहुंचने का समय अगले दिन 23ञ55 बजे।

-ठहरावञ कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी, बक्सर और आरा।

7- एलटीटी-समस्तीपुर साप्ताहिक विशेष

-01043ञ एलटीटी मुंबई से प्रस्थान प्रत्येक गुरुवार 12ञ15 बजे (31.10.2024 और 07.11.2024), समस्तीपुर पहुंचने का समय अगले दिन 21ञ15 बजे।

-01044ञ समस्तीपुर से प्रस्थान प्रत्येक शुक्रवार 23ञ20 बजे (01.11.2024 और 08.11.2024), एलटीटी मुंबई पहुंचने का समय तीसरे दिन 07ञ40 बजे।

-ठहरावञ कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, प्रयागराज छिवकी, आरा, हाजीपुर और अन्य।

8- एलटीटी-प्रयागराज साप्ताहिक विशेष

-01045ञ एलटीटी मुंबई से प्रस्थान प्रत्येक मंगलवार 12ञ15 बजे (29.10.2024 और 05.11.2024), प्रयागराज पहुंचने का समय अगले दिन 11ञ20 बजे।

-01046ञ प्रयागराज से प्रस्थान प्रत्येक बुधवार 18ञ50 बजे (30.10.2024 और 06.11.2024), एलटीटी मुंबई पहुंचने का समय अगले दिन 16ञ05 बजे।

-ठहरावञ कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी।

मप्र में शराब से 16,000 करोड़ की कमाई का टारगेट

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री और डेप्युटी सीएम जगदीश देवड़ा ने हाल ही में शराब कारोबारियों के लिए आबकारी विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में हिस्सा लिया। 17 अक्टूबर को जारी सरकारी अधिसूचना में कहा गया था कि यह बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। देवड़ा ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 16,000 करोड़ रुपये है। कार्यशाला में डेप्युटी सीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी के समन्वित प्रयासों से हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। देवड़ा ने दोहराया कि मध्यप्रदेश में शराब की अवैध बिक्री प्रतिबंधित

है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कड़ी नजर रखी जाएगी। जहां भी अवैध कारोबार या कालाबाजारी की सूचना मिलेगी, वहां दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देवड़ा ने वाणिज्यिक कर विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए डिस्टिलर, शराब निर्माताओं और बार-लाइसेंसधारियों से भी मुलाकात की। जब शराब कारोबारियों और ठेकेदारों ने देवड़ा को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसी भी कठिनाई का समाधान करेगी और आबकारी अधिकारियों को उनके मुद्दों को हल करने का आदेश दिया। देवड़ा ने कहा कि आबकारी विभाग ने ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त शराब व्यापारियों को कई सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे दक्षता, अधिक पारदर्शिता और उच्च राजस्व प्राप्त हुआ है।

वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि बैठक विशेष रूप से शराब के व्यापार को बढ़ावा देने और अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सलाहकार केके मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया कि मप्र में बेटियां और महिलाएं सुरक्षा के लिए रो रही हैं। कहीं बलात्कार, कहीं अपहरण तो कहीं सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं।

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मप्र सरकार के 10 माह पूरे होने पर पूछे सवाल

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 10 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। डॉ मोहन यादव की सरकार से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल पूछे हैं। जीतू पटवारी ने मंगलवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 33 योजनाओं को वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का वोट शिवराज के नाम पर मिला था। डॉ. मोहन यादव को पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री बना दिया। आपको जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आप केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। शिवराज ने जब वोट लिया तब उन्होंने जनता के सामने एक वचन पत्र दिया था। कहा था कि मैं बहनों को हर महीने 3000 दूंगा। हर हालत में दूंगा। आप ने कहा कि हम 5000 तक देंगे। 10 महीने की सरकार में 3000 क्यों नहीं दिया? 450 में गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपकी सरकार को सांप सूंघ गया। जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज ने जो 33 योजनाएं चालू की थीं। मोहन सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दिया। सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन योजनाओं को फंड आवंटन क्यों रोका गया है? पटवारी ने बताया कि आज मंगलवार है। मैं पिछले पांच मंगलवार से शिवराज से समय मांग रहा हूं, क्योंकि वे देश के कृषि मंत्री हैं। चाहे झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा हो जहां चुनाव होते हैं वे मध्यप्रदेश की दुहाई देते हैं। किसानों के हित और अधिकारों की बातें करते हैं।

वे कहते हैं कि वे किसान के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता वे किसान के बेटे हैं, इसमें कितना सच है या कितना झूठ? लेकिन, मैं किसान का बेटा हूं मैं किसान की उस वेदना, पीड़ा और सत्य को शिवराज जी से मिलकर उनसे सकारात्मक बातें करना चाहता हूं।

भोपाल के खेत में काले हिरण का शिकार शव पर गोली लगने जैसा निशान

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। भोपाल के एक खेत में ब्लैक बक यानी, काले हिरण का शव पड़ा मिला है। शव 15 से 20 घंटे पुराना है। शरीर पर गोली जैसा घाव है। आशंका है कि काले हिरण को गोली मारी गई है। शिकार संभवतः सोमवार रात में हुआ है, लेकिन शिकारी शव नहीं ले जा सके। 3 दिन में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आएगी। भोपाल से करीब 40 किमी दूर बरखेड़ा सालम गांव के एक खेत में मंगलवार सुबह काले हिरण का शव पड़े होने की सूचना मिली। वन विभाग की टीम दोपहर में भोपाल के जेल पहाड़ी स्थित पशु अस्पताल में शव लेकर आई। जहां डॉ. संगीता धमीजा ने पोस्टमॉर्टम किया। इसके बाद वन विभाग ने शव का दाह संस्कार किया। काले हिरण के गर्दन के पास गहरा घाव था। इसके अलावा शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं। इससे गोली मारकर शिकार करने की आशंका है। इधर, काले हिरण के शिकार के सवाल पर वन विभाग के जिम्मेदार बचते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीओ धीरज सिंह चौहान ने बताया कि काले हिरण की मौत हुई है। टीम शव लेकर अस्पताल में गई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद बताता हूं। डॉ. धमीजा ने बताया कि बरखेड़ा सालम से वन विभाग की टीम काले हिरण का शव लेकर आई थी। दो डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया है। रिपोर्ट वन विभाग को दे देंगे। शव 15 से 20 घंटे पुराना है। वह वयस्क था। इधर, पोस्टमार्टम करने वाली डॉ. धमीजा भी गोली लगने के सवाल से बचती नजर आई। उन्होंने 2 से 3 दिन में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सीधे वन विभाग को देने की ही बात कही। बता दें कि करीब 5 महीने पहले भी भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित वन विभाग के रेस्ट हाउस के पास एक गर्भवती काले हिरण का शव मिला था। ग्रामीणों का कहना था कि हिरण का शिकार कुत्तों ने किया है। जिस जगह काले हिरण का शव मिला था, उससे आसपास पानी वाला इलाका है। इसके चलते राजस्थानी भेड़ वाले भी वहां भेड़ों को लेकर रुके थे। ऐसी आशंका है कि भेड़ वालों के साथ कुत्ते भी हैं, जो शहरी कुत्तों की तुलना में ज्यादा हिंसक होते हैं। वे भी हिरण पर हमला कर सकते हैं। वहीं, शिकारियों द्वारा भी शिकार करने की बात सामने आई थी।

गड्ढों से उड़ती धूल और अन फिट गाड़ियों ने बिगाड़ी भोपाल की हवा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। सड़कों के गड्ढों से उड़ती धूल और अन फिट गाड़ियों के धुआं से भोपाल की हवा बिगड़ गई है। एआरआई (आघारकर अनुसंधान संस्थान) पुणे, महाराष्ट्र की रिसर्च में यह सामने आया है।

मंगलवार को कमिश्नर संजीव सिंह ने यह रिपोर्ट देखी। उन्होंने सड़कों के निर्माण, रिपेयरिंग,गड्?ढों के भराव, हर महीने पीयूसी जांचने, अन फिट गाड़ियों को हटाने और ईधन की शुद्धता की जांच करने की बात कहीं है। मेसर्स एआरआई पुणे ने भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता के संबंध में एक स्टडी की है, इसमें शहर की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुख्य वायु प्रदूषण कारी कारक एवं प्रतिशत की जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत सड़कों की धूल से पीएम 10- 62.2 प्रतिशत, पीएम 2.5-38 प्रतिशत, यातायात परिवहन पीएम 10-13 प्रतिशत, पीएम 2.5-29 प्रतिशत एवं अन्य पीएम 10-24.8 प्रतिशत, पीएम 2-33 प्रतिशत है।कमिश्नर सिंह ने मंगलवार को कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में शहर वायु गुणवत्ता सुधार के लिए बैठक भी की। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक, आरटीओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शहर में वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए है। सिंह ने आरटीओ एवं ट्रैफिक पुलिस से कहा कि अन फिट वाहनों पर उचित कार्रवाई करें।

तब्लीगी इज्तिमा में इस बार मेट्रो निर्माण का काम बनेगा रुकावट

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। इस बार के सालाना तब्लीगी इज्तिमा में मेट्रो निर्माण का काम रुकावट बनेगा। बैरिकेडिंग की वजह से भोपाल टॉकीज से करोंद नबीबाग तक के पांच किलोमीटर एरिया से ट्रैफिक निकालना मुश्किल होगा। ऐसे में बैरिकेडिंग को संकरी करना पड़ेगा। यह बात इंतेजामिया कमेटी के सदस्यों ने ईटखेड़ी के घासीपुरा इज्तिमा स्थल पर रखी गई तैयारियों की समीक्षा बैठक में कही। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मेट्रो कंपनी के अफसरों के साथ अलग से बैठक रखने की बात कही। बैठक में कलेक्टर ने इज्तिमा के बारे में जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक करीब आठ लाख लोग जमा होते हैं। जबकि आखिरी दिन दुआ में शामिल होने करीब चार लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यह आयोजन दस से बारह लाख लोगों का रहता है। ऐसे में बंदों की तादाद को देखते हुए इंतजाम किए जाएं, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने नगर

निगम, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, फायर अमला और बिजली विभाग सहित अन्य विभागों के अफसरों को अपना-अपना काम समय पर करने की हिदायत दी। इंतेजामिया कमेटी के सदस्य उमर हफीज ने बताया कि इज्तिमा स्थल पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सरकारी अमला भी जल्द ही अपना काम शुरू करेगा। परिवहन विभाग देगा चार सौ बसें भोपाल स्टेशन, रानी कमलापति और बैरागढ़ रेलवे स्टेशन, नादिरा और हलालपुरा बस स्टैंड और अन्य जगहों से बंदों को लाने ले जाने के लिए इस बार परिवहन विभाग ने चार सौ बसें देने की सहमति दी है। कलेक्टर ने इस संबंध में आरटीओ जितेंद्र शर्मा को हिदायत दी कि वह चार सौ बसों का इंतजाम कराएं। दुआ के दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी तैयारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने बताया कि दो दिसंबर को सामूहिक दुआ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए इस दिन स्कूलों की छुट्टी रखी जाएगी। हालांकि, इसके पहले आसपास क्षेत्र के स्कूल अपने स्तर पर छुट्टी रखते थे।

तीन सौ एकड़ एरिया में लगेगा वॉटर प्रूफ पंडाल

इज्तिमा में लगातार बढ़ रही तादाद को देखते हुए इंतेजामिया कमेटी इस बार तीन सौ एकड़ में वॉटर प्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है, जिससे बारिश होने पर भी बंदों को दिक्कत न हो। विदेशों से आने वाले मेहमानों के लिए अलग से इंतजाम किया जाएगा।

सड़क पर नहीं लगेंगी अस्थाई दुकानें

कलेक्टर ने बताया कि करोंद से ईटखेड़ी तक अस्थाई तौर पर दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। इसके साथ मुख्य सड़क पर वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बार भी पार्किंग एरिया बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में 65 जगहों पर पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा।

सम्पादकीय

पश्चिमी प्रभाव वाले 'जी-7' के सामने खड़ी है 'ब्रिक्स' की चुनौती

रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मंगलवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। हमारी गहरी मित्रता है। हमारे संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर हमारा संपर्क बना हुआ है।

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) के नेता समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस के कजान में इकट्ठा हुए हैं। यह पहला मौका है जब ब्रिक्स के नए सदस्य भी वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। इस साल की शुरुआत में ही मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया था। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है। उसने दो दर्जन से अधिक देशों को बतौर पर्यवेक्षक आमंत्रित किया है। इन देशों ने पहले 'ब्रिक्स+' शिखर सम्मेलन के लिए समूह में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। बता दें कि 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है या अपनी इच्छा जताई है। इनमें दक्षिण-पूर्व एशियाई देश थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम, नाटो सदस्य तुर्की, अल्जीरिया जैसे प्रमुख तेल और गैस उत्पादक, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, नाइजीरिया, जिसकी आबादी अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, और दुनिया का आठवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बांग्लादेश शामिल हैं। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मंगलवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। हमारी गहरी मित्रता है। हमारे संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर हमारा संपर्क बना हुआ है। हर समस्या का हल शांति से ही हो सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम ने कहा कि भारत अपने रुख पर कायम है और शांति को लेकर हर संभव सहयोग करेगा। भारत मानवता को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। हम शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी यह दिखाने का एक अवसर है कि यूक्रेन पर अपने युद्ध के लिए मास्को को अलग-थलग करने के पश्चिमी प्रयास सफल नहीं हुए हैं और रूस के दुनियाभर में मित्र हैं। ब्रिक्स के नेता रूस और चीन का लक्ष्य पश्चिमी नेतृत्व वाली सुरक्षा और वित्तीय ढांचे का विकल्प बनाना है और अपने समूह का विस्तार करना भी है, जिससे पूरी दुनिया में ब्रिक्स का दबदबा बढ़े और पश्चिमी प्रभाव को कम किया जा सके। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस उभरते समूह ब्रिक्स में शामिल होने के स्पष्ट आर्थिक लाभ हैं। ब्रिक्समें शामिल 10 देश दुनिया की 45 प्रतिशत आबादी, दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 28 प्रतिशत और वैश्विक कच्चे तेल का 47 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स के भीतर व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समूह ने अपनी जगह बनाई है। जून 2024 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से निकले एक संयुक्त बयान में ब्रिक्स सदस्यों के बीच 'व्यापार और वित्तीय लेन-देन में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने' को प्रोत्साहित किया गया। 1992 के बाद से आर्थिक परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया है। जी-7 राष्ट्रों की वैश्विक जीडीपी में 45.5त्न हिस्सेदारी थी, जबकि ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी केवल 16.7त्न थी। 2023 में, ब्रिक्स ब्लॉक की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी अब 37.4त्न है, जबकि जी-7 की हिस्सेदारी 29.3% है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतर बढ़ रहा है और यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रिक्स राष्ट्र वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 40त्न से अधिक योगदान करते हैं, और उनकी सामूहिक आर्थिक वृद्धि दर इस वर्ष 4त्न तक पहुंचने का अनुमान है - जो जी-7 देशों के लिए 1.7त्न की वृद्धि पूर्वानुमान और 3.2% वैश्विक औसत से काफी अधिक है।
पुतिन के अनुसार, ब्रिक्स ब्लॉक दुनिया के लगभग 25% निर्यात के लिए जिम्मेदार है।

दक्षिणी राज्यों में आबादी बढ़ाने की 'आवाज' के मायने

जापान, चीन और कुछ यूरोपीय देश पहले ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जहां बुजुर्गों की संख्या अधिक है। दक्षिण भारत में यह समस्या और गंभीर है क्योंकि युवा रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं। परिणामस्वरूप कई गांवों में तो अब बुजुर्ग ही रह गए हैं। नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर 1.6 तक गिर चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। अगर यह और घटती है, तो 2047 तक बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, जो कि वांछनीय नहीं है।

देश के दक्षिणी राज्यों से आबादी बढ़ाने की जो आवाजें उठी हैं, क्या वो 'जनसंख्या जिहाद' का पलटवार है या भविष्य में राजनीतिक सत्ता सूत्र अपने हाथों में रखने की प्री प्लानिंग है अथवा देश में क्षेत्रवार आबादी के असंतुलन से होने वाले व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के मद्देजर ऐहतियाती उपाय अभी करने का आग्रह है, इसे हमे गहराई से समझना होगा। दक्षिणी राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों ने हाल में अपने प्रदेश के लोगों से आबादी बढ़ाने की जो अपील की है, वो भारत में 'जनसंख्या विस्फोट' को रोकने के लिए अब तक चली आ रही 'परिवार नियोजन' थ्योरी के ठीक विपरीत है। तो क्या इन नेताओं को बेतहाशा बढ़ती आबादी से जुड़े खतरों का भान नहीं है या फिर वो सीमित परिवारों के आग्रह में छिपे आसन्न खतरों को भांप कर ऐसा कह रहे हैं? आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल में कहा कि अब उनकी सरकार पुराने कानून में बुनियादी बदलाव कर उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देगी, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों। अभी तक दो से ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। नायडू ने इस के पक्ष में दलील दी कि वृद्धावस्था की समस्या के संकेत दक्षिण भारत, खासतौर से आंध्रप्रदेश में दिखने लगे हैं।

जापान, चीन और कुछ यूरोपीय देश पहले ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जहां बुजुर्गों की संख्या अधिक है। दक्षिण भारत में यह समस्या और गंभीर है क्योंकि युवा रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं। परिणामस्वरूप कई गांवों में तो अब बुजुर्ग ही रह गए हैं। नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर 1.6 तक गिर चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। अगर यह और घटती है, तो 2047 तक बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, जो कि वांछनीय नहीं है।

चंद्रबाबू के बयान के दूसरे ही दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने भी लगभग उसी बात को दोहराया। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा- संसदीय परिसीमन प्रक्रिया से दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने और छोटा परिवार का विचार छोड़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अतीत में, बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 बच्चों का नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति अर्जित करने और खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देते थे। अब उन्हें सचमुच 16 बच्चे पैदा करने चाहिए, न कि एक छोटा और खुशहाल परिवार रखना चाहिए।

वैसे नायडू के कथन में सच्चाई है कि बेशक आज भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 65 फीसदी 35 साल के नीचे की है। लेकिन तीस साल बाद यही आबादी 65 वर्ष की होगी। यानी भारत में हर पांचवा शख्स बुजुर्ग होगा। यह आबादी करीब 35 करोड़ होगी। यह वो आबादी होगी, जो सेवानिवृत्त अथवा कम कार्यक्षम लोगों की होगी।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां आबादी का अर्थ जनशक्ति से ज्यादा 'वोट' हो चुका है, वहां जनसांख्यिकीय संतुलन का अर्थ राजनीतिक सत्ता को कायम रखना अथवा बदलने की ताकत से है। जब से देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति हावी हुई है, तब से यह जनसंख्या संतुलन के प्रति यह नजरिया और उग्र हुआ है। यह भावना तेजी से गहरा रही है कि किसी विशेष धर्म, जाति अथवा समुदाय की संख्या से ही सियासी शक्तिसे अर्जित किया जा सकता है और उस पर पकड़ बनाई रखी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि राज्य में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हम यूपी पर राज करेंगे। इसमे सच्चाई कितनी है, यह अलग बात है। लेकिन भावनात्मक स्तर पर यह भी एक तरह का 'जनसंख्या जिहाद' ही है। प्रकारांतर से आबादी को बढ़ाना सत्ता में रहने का रामबाण नुस्खा है। याद करें, उस नारे को जिसमें यह आह्वान किया गया है ' जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।'

इसका सीधा अर्थ यही है कि न केवल सत्ता बल्कि सामाजिक और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और वर्चस्व के लिए जरूरी है कि आपकी संख्या अन्य से ज्यादा हो। वरना आप की स्थिति दोयम दर्जे की हो सकती है। संभव है कि आप कहीं भी निर्णायक स्थिति में रहें। यह डर केवल काल्पनिक है, ऐसा भी नहीं है। देश में जहां जहां धार्मिक आधार पर जनसांख्यिकी बदली है, वहां अलगाववाद और विभाजन की दरारें गहराने लगी हैं। और यह केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, लोकतंत्र और व्यक्ति और अभिव्यक्त स्वातंर्त्य के घोर समर्थक यूरोपीय देशों में भी हो रहा है।

हालांकि कुछ लोग इसे केवल मिथक मानते हैं, लेकिन देश में बहुसंख्य हिंदुओं की आबादी वृद्धि दर में गिरावट को लेकर आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक के.सी. सुदर्शन ने 2000 में ही इस मुद्दे को उठाया था। 8 साल पहले संघ प्रमुख डॉ.मोहन भागवत ने भी कहा था कि बहुसंख्य हिंदुओं की घटती आबादी चिंता का विषय है। उन्होंने युवा दंपतियों से आग्रह किया था कि वो दो से ज्यादा बच्चे पैदा करें। लगभग यही बात हाल में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने भी कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में उसी का राज चलता है, जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होती है। इसी तरह और भी हिंदू साधु संत इस तरह के आह्वान करते रहते हैं। ऐसी बातों का प्रजनन योग्य युवाओं पर कितना असर होता है, यह स्वतंत्र अध्ययन का विषय है, क्योंकि नेताओं संतो के आग्रह में यह कहीं स्पष्ट नहीं होता कि ज्यादा बच्चे पैदा करने के बाद उनके समुचित पालन पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए जरूरी संसाधन कहां से आएंगे? बच्चों की अच्छी परिवरिश में होने वाले कष्टों में हिस्सेदारी कौन और कैसे करेगा? या केवल आबादी बढ़ाने के चक्कर में वो ऐहिक जीवन दांव पर लगा दें?

वैसे भी जो नेता, सामाजिक संगठनों के प्रभावी पुरूष और साधु संत ऐसे आह्वान करते रहते हैं, उनका लोगो और खासकर हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में निजी स्तर पर कोई खास योगदान नहीं है। या तो वे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते या फिर अपने संसाधनो को बंटने नहीं देना चाहते। खुद चंद्रबाबू नायडू का एक बेटा है और स्टालिन की सिर्फ दो संतानें हैं। प्रचारक और साधु संतों के परिवार ही नहीं होते। इनमें केवल राजद नेता लालू प्रसाद को अपवाद माना जा सकता है, जिन्होंने अपनी तमाम राजनीतिक सक्रियता के बावजूद परिवार विस्तार के मोर्चे को कमजोर नहीं होने दिया और 9 संतानों के पिता बने। हालांकि लालू ने कभी दूसरों को ऐसा करने की सार्वजनिक सलाह नहीं दी।

एक समय था, जब देश की आबादी आज से भी आधी थी और चौतरफा हम दो हमारे दो का शोर था। कहा जा रहा था कि एक गरीब देश भारी आबादी के बोझ को सह नहीं सकता। लेकिन हमने इतनी तरक्की तो कर ली है कि देश आज 145 करोड़ की आबादी को भी खिला रहा है। तो फिर और आबादी बढ़ाने की बात क्यो की जा रही है? इसके कई पहलू हैं। पहला तो राजनीतिक है। 2026 में देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का आबादी के अनुसार नए सिरे से परिसीमन होना है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर आबादी को ही आधार माना गया तो लोकसभा की वर्तमान सीटें 543 से बढ़कर 888 होने वाली हैं। इनमें सर्वाधिक सीटे सबसे ज्यादा आबादी वाले यूपी में बढ़ेंगी, जो वर्तमान की 80 से बढ़कर 147 हो जाएंगी। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पं.बंगाल और मप्र का नंबर है। ये सभी उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्य हैं। ऐसे कुल 18 राज्यों में वर्तमान में लोस की फिलहाल 382 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद 688 हो सकती हैं, जबकि दक्षिण के पांच राज्यों में वर्तमान में 129 सीटें हैं, जो बढ़कर 184 ही होंगी। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों की सीटों में भी मामूली बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि उनकी आबादी वृद्धि दर बहुत कम है। तो क्या आबादी का ज्यादा न बढ़ना, खुशहाली की गारंटी भले हो, लेकिन राजनीतिक सत्ता संतुलन में एक नकारात्मक फैक्टर है? दक्षिण के राज्यों का यह सवाल वाजिब है कि अगर उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को काबू में रखकर आर्थिक मोर्चे पर तेजी से तरक्की की तो क्या यह उनका अपराध है, बनिस्बत उन उत्तर और राज्यों के जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विकास की दौड़ में वो दक्षिणी राज्यों से अभी भी पीछे हैं।

डर यह है कि नए परिसीमन के बाद कम आबादी के कारण केंद्रीय सत्ता में दक्षिणी राज्यों की भागीदारी कम होती जाएगी, जो एक संघ राज्य के लिए ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में न्यून भागीदारी अलगाववाद की भावना को बढ़ा सकती है और एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा इससे खंडित हो सकती है। यह डर इसलिए भी है कि बीजेपी जैसी कोई पार्टी केवल उत्तर पश्चिमी राज्यों से ही इतनी सीटें जीत लेगी कि सत्ता हासिल करने के लिए उसे दक्षिणी राज्यों की जरूरत ही न पड़े। दूसरे, आबादी के असंतुलन का सामाजिक ,सांस्कृतिक और आर्थिक परिणाम भी होगा। न केवल विभिन्न धार्मिक समुदायों में बल्कि खुद हिंदू समाज में भी। यहां प्रश्न यह भी है कि लोग कितने बच्चे पैदा करें, या न करें, कैसे करें, इसमें सरकारों को दखल देना चाहिए या नहीं? चीन का उदाहरण सामने है। उसे जनसंख्या और लैंगिक असंतुलन के चलते अपनी 35 साल पुरानी 'एक परिवार, एक बच्चा' नीति बदलनी पड़ी और दो बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। इसके बाद भी वहां युवा दंपति बच्चे पैदा करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। भारत में भी स्थिति काफी कुछ वैसी ही बनती जा रही है, क्योंकि अब बच्चा पैदा करना केवल मर्दानगी अथवा मातृत्व क्षमता का सवाल भर नहीं है, बच्चों की परवरिश कैसे करें, यह प्रश्न भी पहाड़ जैसा है।

झारखंड में 24 साल में 13 सरकार, सात चेहरों के इर्द-गिर्द घूमती रही सत्ता

झारखंड में दो चरण में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 13 और 20 नवंबर को झारखंड के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तमाम पार्टियां चुनावी परीक्षा में जाने से पहले अपने चेहरों को चुनने के लिए मंथन कर रही हैं। दिल्ली से लेकर झारखंड तक बैठकों को दौर जारी है। फिलहाल, एनडीए के दल भाजपा और आजसू तो दूसरी ओर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। झारखंड ने बीते पांच साल में दो व्यक्तियों को तीन बार मुख्यमंत्री बनते देखा है। साल 2000 में झारखंड के गठन के बाद यहां भाजपा या झामुमो के नेतृत्व में ज्यादातर सरकारें बनी हैं। 24 साल में 13 अलग-अलग सरकारें बन चुकी हैं। इन सरकारों का नेतृत्व सात अलग-अलग व्यक्तियों ने किया है।

लंबे समय तक बिहार का हिस्सा रहा झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना। साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम के जरिये झारखंड का निर्माण किया था। उस वर्ष की शुरुआत में बिहार में हुए चुनाव के आधार पर झारखंड की पहली विधानसभा के गठन का आधार बना। इन चुनावों के आधार पर भाजपा ने सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य में पहली सरकार बनाई। 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

मुख्यमंत्री बनने से पहले मरांडी दूसरी और तीसरी वाजपेयी सरकार में पर्यावरण और वन राज्य मंत्री रह चुके थे। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा उपचुनाव जीता। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल ढाई साल तक चला। मरांडी की जगह उनके मंत्रिमंडल में भाजपा के एक मंत्री अर्जुन मुंडा आए, जो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने। मुंडा 2005 में पहली विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक मुख्यमंत्री बने रहे। अर्जुन मुंडा तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 2005 में राज्य में पहली बार चुनाव हुए। जब नतीजे सामने आए तो सत्ताधारी भाजपा और उसका गठबंधन 41 सीटों के जादुई आंकड़ों से पिछड़ गया। भारतीय जनता पार्टी को 23.57त्न मत के साथ सबसे ज्यादा 30 सीटें आईं। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17 सीटें और 14.29त्न मत हासिल किए। नौ सीटें जीतकर कांग्रेस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसे 12.05त्न वोट मिले। अन्य दलों की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के सात, जदयू के छह और आजसू के दो उम्मीदवार जीते। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य दलों के कुल 10 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे।

इस तरह से झारखंड की जनता ने किसी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। झामुमो के नेता शिबू सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन आवश्यक संख्या नहीं जुटा सके। इसलिए सीएम के रूप में शपथ लेने के 10 दिन के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया और मार्च 2005 में दूसरी बार सीएम बने।

हालांकि, अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार केवल डेढ़ साल तक ही चल पाई। गठबंधन के टूटने के कारण सितंबर 2006 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जेएमएम के समर्थन वाली एक और गठबंधन सरकार ने राज्य की सत्ता संभाली। झारखंड में पहली बार सरकार का नेतृत्व एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा ने किया। कोड़ा जब सीएम बने तब उनकी उम्र करीब 35 साल थी। कोड़ा सरकार को झामुमो और अन्य दलों का समर्थन हासिल था। करीब दो साल बाद झामुमो ने समर्थन वापस ले लिया और मधु कोड़ा की सरकार गिर गई। इसके बाद झामुमो के नेता शिबू सोरेन अगस्त 2008 में दूसरी बार सीएम बने। सोरेन जब सीएम बने, तो वे लोकसभा सांसद थे। सीएम बने रहने के लिए शिबू सोरेन को उपचुनाव लड़ना पड़ा। जनवरी 2009 में सोरेन उपचुनाव हार गए, जिसके चलते उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। दिसंबर 2009 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहा, जब झारखंड में दूसरी बार चुनाव हुए।

दूसरे चुनाव के बाद भी कई बार सरकारें बनीं और गिरीं

2009 में राज्य में दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुए। जब नतीजे सामने आए तो कोई भी दल 41 सीटों के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाया। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 20.18त्न मत के साथ 18 सीटें आईं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 18 सीटें मिलीं लेकिन इसने 15.20त्न मत हासिल किए। 14 सीटें जीतकर कांग्रेस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसे 16.16त्न वोट मिले। बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के 11 विधायक चुनकर आए और इसे 8.99त्न मत मिले। अन्य दलों की बात करें तो राजद और आजसू के पांच-पांच और जदयू के दो उम्मीदवार जीते। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य दलों के कुल आठ प्रत्याशी चुनाव जीते। खंडित जनादेश के कुछ महीनों बाद झामुमो, भाजपा ने अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया। सोरेन का तीसरा कार्यकाल करीब पांच महीने (दिसंबर 2009-मई 2010) तक चला और भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद सितंबर 2010 में भाजपा के अर्जुन मुंडा तीसरी बार सीएम बने। लेकिन अर्जुन मुंडा सरकार का तीसरा कार्यकाल जनवरी 2013 में ही समाप्त हो गया। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन सीएम बने। झामुमो-कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार डेढ़ साल तक चली।

2014 के नवंबर में राज्य में तीसरी बार विधानसभा चुनाव हुए। 81 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने सबसे अधिक 37 सीटें जीतीं जिसने 31.26त्न वोट हासिल किए। इसके बाद झामुमो को 17 सीटें मिलीं इसके खाते में 20.43त्न मत गए। आठ विधायकों के साथ झाविमो (प्रजातांत्रिक) तीसरे स्थान पर रही जिसके पास 9.99त्न वोट गए। कांग्रेस के 10.46त्न वोट के साथ छह विधायक तो आजसू के 3.68त्न वोट के साथ पांच विधायक जीते। इसके अलावा छह अन्य विधायक भी चुनकर विधानसभा पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुबर दास ने दिसंबर 2014 में बतौर सीएम शपथ ली। उनकी सरकार ने राज्य के इतिहास में पहली बार पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर 2019 के बीच पांच चरणों में हुए थे। इसमें कुल 65.18 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था। नतीजे 23 दिसंबर 2019 को घोषित किए गए। जब नतीजे सामने आए तो सत्ताधारी भाजपा को झटका लगा और वह 41 सीटों के जादुई आंकड़ों से पिछड़ गई। हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो को सबसे ज्यादा 30 सीटें आईं और इसे 18.72त्न वोट मिले। इसके बाद भाजपा को 25 सीटें मिलीं जिसने 33.37त्न मत हासिल किए। अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस के 16 विधायक (13.88त्न वोट), झाविमो के तीन (5.45त्न वोट) और आजसू के दो विधायक (8.1त्न वोट) जीते। इसके अलावा दो निर्दलीय विधायक जबकि राजद, भाकपा (माले) और एनसीपी के एक-एक विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। हार के बाद भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे रघुबर दास ने इस्तीफा दे दिया। झामुमो के नेतृत्व में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार में झामुमो को कांग्रेस, राजद, सीपीआई (एमएल) और एनसीपी का साथ मिला। इसके अलावा झाविमो प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन सरकार को अपनी पार्टी का समर्थन दे दिया। इसके बाद 29 दिसंबर को झामुमो विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फरवरी 2020 में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी घर वापसी करते हुए भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) का भाजपा में विलय भी कर दिया।

वहीं हेमंत सोरेन का दूसरा कार्यकाल काफी चुनौतियों वाला रहा। 2022 में चुनाव आयोग ने झारखंड के तब के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी जिसमें मांग की गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा देकर चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाए। हालांकि, इस याचिका पर बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हेमंत की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुईं। 31 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोपों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से ऐन पहले उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया और राज्य की कमान शिबू सोरेन के करीबी माने जाने वाले चंपई सोरेन को मिली। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पांच महीने से रांची की जेल में बंद हेमंत को 28 जून को बड़ी राहत मिल गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। इसके बाद झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और अदालत से राहत मिलने के बाद हेमंत ने चंपई की जगह ली। 4 जुलाई को हेमंत तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए।

हालांकि, हेमंत सोरेन के झारखंड की सत्ता संभालने के बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई के पाला बदलने की पटकथा शुरू हो गई। अगस्त मध्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने भाजपा नेताओं से मुलाकात की। चंपई ने 18 अगस्त को एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा जिससे तय हो गया कि वह झामुमो से अलग होंगे। चंपई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया। 26 अगस्त को चंपई नई दिल्ली पहुंचे जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से फिर मुलाकात की। पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

बीकेएसएन कॉलेज में तीन दिवसीय युवा उत्सव का हुआ शुभारंभ

युवा इस मंच के माध्यम से सृजनात्मकला और ऊर्जा का विकास करेंगे: प्रचार्य

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ ।

शाजापुर, बीकेएसएन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में मंगलवार को तीन दिवसीय महाविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में मंचासीन अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रवलित किया गया। वहीं विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना एवं सांस्कृतिक गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ बीएस विभूति ने की। कार्यक्रम में प्राचार्य ने कहा कि युवा इस मंच के माध्यम से सृजनात्मकला और ऊर्जा का विकास करेंगे। युवा उत्सव कार्यक्रम संयोजक प्रो हरेंद्रसिंह गुर्जर ने स्वागत भाषण दिया। इसके साथ ही उन्होने विद्यार्थियों को युवा उत्सव के बारे

में बताते हुए आगामी तीन दिवसों तक चलने वाले कार्यक्रमों की रुपरेखा से अवगत कराया। प्रोफेसर हरेंद्रसिंह गुर्जर ने कहा कि युवा उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक ऐसा सामूहिक अवसर एवं मंच प्रदान करना है जिससे वे अपनी संगीत, कलात्मक, रूपांकन, रंग मंचीय एवं साहित्यिक क्षमता व प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकें। युवा उत्सव के प्रथम दिवस रंगोली, वाद-विवाद भाषण प्रतियोगिता, एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकांकी नाटक, मूक अभिनय, हास्य नाटिका, मिमिक्री तथा प्रश्न मंच जैसी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। युवा उत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन एकल गायन की विभिन्न प्रतियोगिताएं, समूह गायन, चित्रकला, कोलाज पोस्टर निर्माण, व्यंग्य चित्र निर्माण, मूर्ति शिल्प आदि की प्रतियोगिता आयोजित होंगी। युवा उत्सव का समापन 24 तारीख को पुरुस्कार वितरण के साथ होगा। युवा उत्सव में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा।

एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा संत विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भिंड जनपद का टॉप स्कूल घोषि

नंबर वन रैंकिंग के लिए चेयरमैन डॉ. विवेक यादव गुड़गांव में पुरस्कृत, प्रिंसिपल गीता रेड्डू भी रही मौजूद

आदित्य द्विवेदी । सिटी चीफ ।

भिंड, संत विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भिंड को देश की प्रतिष्ठित संस्था एजुकेशन वर्ल्ड ने रैंकिंग के आधार पर भिंड जनपद का टॉप यानी नंबर वन स्कूल घोषित करते हुए सम्मानित किया गया है। गुडगाँव के द लीला एंबिएंस गुरुग्राम होटल एंड रेजिडेंसी में 19 अक्टूबर को संत विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भिंड को इसके लिए एजुकेशन वर्ल्ड संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया। संत विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भिंड के चेयरमैन डॉ. विवेक यादव और रिंसिपल गीता रेड्डू ने स्वयं मौजूद रहकर यह पुरुस्कार प्राप्त किया। पुरस्कृत किए जाने पर अनेक हस्तियों ने संत विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भिंड और उसके प्रबंध तंत्र को बधाई दी है। संत विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भिंड के चेयरमैन डॉ. विवेक यादव और प्रधानाचार्या गीता रेड्डू ने इस पुरस्कार के लिए पूरी संत विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भिंड टीम और संत विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भिंड के सभी अभिभावकों और ब'चों को बधाई दी है।

शाजापुर में पांच दिवसीय गरबा गीत भजन गायन का हुआ आयोजन

राष्ट्रीय भजन गायक धौलपुरे पार्टी ने दी देवी गीत की प्रस्तुति

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ ।

शाजापुर, संत शिरोमणि सद्गुरू रविदास समाज सेवा समिति एवं अंबे माता गरबा उत्सव समिति के द्वारा वार्ड नंबर 5 संत रविदास मोहल्ला भैरू महाराज मंदिर प्रांगण में लगभग 45 वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा पर मां अंबे की 'योत खड़ी कर पांच दिवसीय गरबा गीत भजन गायन का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन का सोमवार रात भजन गीत के साथ समापन हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुति में प्रसिद्ध राष्ट्रीय कबीर भजन गायक दिनेशकुमार धौलपुरे, बाबूलाल धौलपुरे एवं टीम द्वारा देवी गीतों से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद लोकगीत, कबीर भजन, मीराबाई के भजन, रविदास जी के भजन आदि की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा विष्णु धौलपुरे, दिलीप धौलपुरे, सामाजिक जन विक्रम अहिरवार, ओमप्रकाश परमार, दयाराम, घनश्याम, कालू महाराज, रामप्रसाद धौलपुरे, सुनील, मनोहरलाल, सत्यनारायण, कैलाश आदि उपस्थित थे।

जिले में 52 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी का रकबा

हो रहा है 10,33,180 मैट्रिक टन का उत्पादन

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, जिले में उद्यानिकी फसलों को किसानों द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है जिसके चलते यहां 52 हजार 822 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलें लगाई गईं जिससे 10 लाख 33 हजार 180 मैट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त हो रहा है। उपसंचालक उद्यानिकी मनीष चौहान ने बताया कि जिले में प्याज, आलू, संतरा, लहसून एवं धनियां फसल प्रमुखता से उगाई जाती हैं। शाजापुर जिले के किसान प्याज, आलू एवं संतरा फसल को स्थानीय मंडियों के साथ-साथ इन्दौर, दिल्ली, कानपुर, जयपुर में विक्रय के साथ ही बांग्लादेश एवं नेपाल में भी निर्यात करते हैं। जिले में 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पीडीएमसी योजना अंतर्गत अनुदान सहायता पर प्रदाय मिनी स्प्रिंकलर एवं ड्रिप संयंत्रों से कृषक उद्यानिकी की खेती कर रहे हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता एवं उत्पादन में काफी सुधार हुआ है। इसके साथ ही जिले में वर्षाजल को संरक्षित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान सहायता एवं स्वयं के व्यय से लगभग 4×4 प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फॉर्म पौण्ड निर्मित हैं जिससे लगभग 1800 हेक्टेयर उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल में पर्याप्त सिंचाई सुविधा विकसित हुई है। इसी क्रम में जिले में विभागीय 50 प्रतिशत अनुदान पर 495 प्याज भण्डार गृह कृषकों के यहां निर्मित हुए हैं, जिससे 24750 मैट्रिक टन क्षमता में प्याज का सुरक्षित भण्डारण बढ़ा है। जिले के विकासखण्ड मो बड़ोदिया के ग्राम खोरियाएमा एवं आसपास के ग्रामों में 125 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, पीडीएमसी योजना एवं स्वयं कृषकों के द्वारा प्लास्टिक मल्चिंग एवं ड्रिप पद्धति से विभागीय तकनीकि मार्गदर्शन द्वारा मिर्च फसल का नवीन क्लस्टर विकसित किया गया है, जिससे किसानों की आय में अतिरिक्त वृद्धि हुई है। योजना अंतर्गत जिले में मसाला उत्पाद, डेरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, फ्लोर मिल, क'ची घानी तेल, पापड़ उद्योग एवं एनीमल फिड से संबंधित इकाईयां स्थापित होकर उत्पादों का उत्पादन एवं विक्रय कार्य किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं जागरूकता बाबत् विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में लगातार प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशालाएं, बायर सेलर मीट, कृषक संगोष्ठियां की जा रही हैं, जिससे की कृषक अपनी फसल के उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण का कार्य भी करें, ताकि खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सकें।

अनूपपुर कोतवाली पुलिस को मिली सफलता

छात्रावास से लापता हुई 24 वर्षीय नवयुवती को रायपुर (छ.ग.) से किया दस्तयाब

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ । अनुपपुर, दिनांक 08.09.2024 को थाना अमरकंटक अंतर्गत निवासी ग्रामीण ने थाना कोतवाली अनूपपुर में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 24 वर्षीय पुत्री अनूपपुर के एक हास्टल में रहकर सिलाई संबंधित कोर्स कर रही थी जो अचानक ब'ची के हास्टल से कही चले जाने एवं मोबाईल बंद रहने पर मालूम चला कि वह बिना बताये हास्टल से कही चली गई है उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में गुम इंसान क्र. 124/24 पंजीबद्ध किया जाकर जांच तलाश की गई। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान के निर्देशन में थाना कोतवाली अनूपपुर से सहायक उपनिरीक्षक हरूननिशा एवं सहायक उपनिरीक्षक संतोष पाण्डेय के द्वारा उक्त नवयुवती को रायपुर छ.ग. के थाना पुरला अंतर्गत सरोरा बजार से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की गई है एवं नवयुवती को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया है।

राम कथा आयोजन में सहयोग के प्रति समाजसेवी पार्षद पवन चीनी ने भेट किए 61000 नगद की राशि

आस्था के प्रति सहयोग मेरी पहली प्राथमिकता - पार्षद पवन चीनी

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ ।

अनूपपुर, जिले मुख्यालय में भव्य स्तर पर श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है जिसकी शुरुआत 19 नवंबर से 27 नवंबर के मध्य अमरकंटक रोड चंदास नदी के तट पर तय किया गया है। जिसकी भव्य तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और पूरे जिले के हर जगह सेवा समिति के लोग आम नागरिकों से मुलाकात करके सामाजिक आर्थिक और नैतिक रूप से सहयोग की अपेक्षा भी कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम की भव्यता बनी रहे। श्री राम कथा सेवा समिति में सैकड़ो नवयुवक बढ़ - चढ़कर भाग ले रहे हैं और अनेकों प्रकार की तैयारी कर रहे हैं । राम कथा आम लोगों के जीवन पर प्रभाव तो छोड़ते ही हैं आज के नव युवकों को एक सिख देकर चले जाने की बात कह रहे हैं क्योंकि आज सबसे 'यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो अध्यात्म और धर्म की ताकि आम रूप से छोटे-छोटे नवयुवक जो नशे की तरफ भाग रहे हैं वह धर्म और संस्कृति के प्रति जागृत होकर अपने जीवन को नहीं दिशा दे सके इसके लिए समिति के द्वारा लोगों से जुड़कर आर्थिक सहयोग से लेकर धार्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

राम सेवा समिति ने पवन चीनी के पूरे परिवार को दिया आशीर्वाद-

19 नवंबर से प्रारंभ होने वाले श्री राम कथा में कथा वाचक श्री पू'य प्रेमभूषण महाराज के द्वारा कथा वाचन किया जाना है इस बात पर जब सहयोग के लिए श्री राम कथा के समिति के द्वारा अमलाई नगर परिषद भ्रमण के लिए गए तो वहां समाजसेवी व नगर परिषद् बरगवां अमलाई के वार्ड क्रमांक 07 के पार्षद व भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पवन चीनी से मुलाकात की है जहां पर उन्होंने श्री राम कथा के भव्य आयोजन और ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए उन्होंने 61000 रुपए की राशि श्री राम कथा समिति को प्रदान किया है, जिसके लिए श्री राम कथा समिति ने अपने फेसबुक और ब्लॉक के माध्यम से पवन चीनी मित्र मण्डली और उनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया है जिसकी जगह- जगह चर्चा हो रही है निश्चित रूप से धार्मिक कार्यों में समाजसेवी पार्षद पवन चीनी का कार्य हमेशा यादगार रहता है चाहे वह राम कथा हो या फिर राम जी की दीपावली मनाने की बात या कृष्ण भक्ति की बात समय-समय पर गणपति तो दीपावली और दशहरे के मौके पर आनेको कार्य कर समाज में धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी आस्था दिखने में कोई कमी नहीं करते हैं जिसके लिए श्री राम सेवा समिति ने पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया है

एकल अभियान अंचल अनूपपुर में अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा दो दिवसीय अंचल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई संपन्न

विजेता बालक बालिकाओं को ट्रॉफी, मेडल, प्रतिभागी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ

अनूपपुर, यह प्रतियोगिता दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को अनूपपुर में उद्घाटन हुआ । प्रतियोगिता में अनूपपुर, कोतमा बिजुरी ,जैतहरी, पुष्पराजगढ़ ,पौड़ी , दमहेडी,करपा ,बेनीबारी से लगभग ×00 बालक बालिका भाग लिए जिसमें कबड्डी में बालक वर्ग बेनिवारी प्रथम स्थान और दूसरा स्थान करपा रहा ,वहीं बालिका वर्ग में प्रथम स्थान दमेहडी और दूसरा स्थान पुष्पराजगढ़ रहा इसके अलावा दौड़ ,ऊंची कूद ,लंबी कूद ,कुश्ती ,व्यायाम योग का प्रतियोगिता हुआ जिसमें अनेकों बालक बालिकाओं ने भाग लेकर उत्तम स्थान प्राप्त किये, प्रतियोगिता में दिनेश कुमार चंदेल विकासखंड समन्वयक खेल युवा कल्याण विभाग जैतहरी स्टेट रेफरी नेशनल ट्रेनर का सभी खेलों में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ ,प्रतियोगिता का समापन में ×6 विजेता बालक बालिकाओं को ट्रॉफी कप गोल्ड मेडल सिल्वर ब्रांच मेडल एवं सभी प्रतिभागी बालक बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया वहीं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन समिति के द्वारा सभी प्रतिभागी ब'चे आचार्य, सेवावृती कार्यकर्ता ,नगर के सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया।

कटनी में चलती ऑटो लगी आग, मची अफरा-तफरी

ऑटो चालक ने भागकर बचाई अपनी जान

सुनील यादव । सिटी चीफ । कटनी, कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र शासकीय जिला चिकित्सालय के पास एक चलती हुई सवारी ऑटो में आग लग गई, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। यह घटना वक्त हुई जब ऑटो मुड़वारा स्टेशन से होते हुए शासकीय जिला चिकित्सालय के पास पहुंची और अचानक शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली, जो डीजल टैंक तक पहुंच गईं। आग लगनें की जानकारी लगते ही ऑटो चालक ने तत्परता से भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही की ऑटो में कोई सवारी नहीं थी जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हों सका, इस आगजनि में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।स्थानीय लोगों ने जब आग की लपटें उठती देखी, तो उन्हें तत्काल चिंता हुई। आसपास के मेडिकल संचालको और मिस्टर चाट भंडार की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया।

स्वस्थ मुस्कान की दिशा में एक अनोखा कदम

निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर है हुआ आयोजन

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ । सतना, ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल,जबलपुर ने अपने सभी छात्रों और उनके भाई-बहनों के लिए एक निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिससे उन्हें स्वस्थ मुस्कान की दिशा में एक कदम बढ़ाने में मदद मिली। यह शिविर सभी के लिए खुला था, और इसका उद्देश्य ब'चों को दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। पर्ल मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक के अनुभवी डॉक्टर निश्कर्ष जैसवाल और श्रीमती प्रज्ञा जैसवाल ने सभी ब'चों का निशुल्क दंत चिकित्सा जांच की और उन्हें अपने मुंह और दांतों को स्वस्थ रखने की जरूरी जानकारी दी। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती नम्रता कुंदनानी के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में सभी ब'चों को निशुल्क टूथपेस्ट डॉक्टर द्वारा दिए गए। इस मौके पर ब'चों के अभिभावक द्वारा इस अनोखे आयोजन की सराहना की गयी और बताया गया कि इस स्कूल की यह विशेषता है कि यहां स्कूल में पढ़ रहे ब'चों की उ'जवल भविष्य के साथ साथ, समय-समय पर समाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद , एवं हर त्यौहार का आप के जीवन में क्या महत्व है ब'चों को बताया जाता है , लेकिन अब स्वास्थ्य से संबंधित , मुंह एवं दंत चिकित्सा जांच का जो आयोजन किया गया है, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है, ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल द्वारा आयोजित कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं,

- अनुभवी डॉक्टर द्वारा निशुल्क दंत चिकित्सा जांच,
- दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता,
- निशुल्क टूथपेस्ट का वितरण,

चेतना ने जगाई नई चेतना

राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए भेजा गया महिला फुटबॉल टीम में

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ सतना, कोठी के समीपी ग्राम रनेही निवासी चेतना तिवारी की चेतना से गांव सहित माता-पिता का नाम रोशन हुआ है, रनेही ग्राम निवासी राकेश तिवारी की पुत्री चेतना तिवारी ने अपने दमदार प्रदर्शन के बदौलत महिला फुटबॉल की सीनियर टीम के लिए राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुई है जिससे क्षेत्र में अत्यंत हर्ष व्याप्त है, प्रदेश स्तरीय जूनियर महिला फुटबॉल खेल में चेतना तिवारी के अ'छे खेल की बदौलत प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने चेतना को राष्ट्रीय स्तर पर मौका प्रदान किया है और अब वह अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए हैदराबाद पहुंची है और राष्ट्रीय स्तर के खेल पर सीनियर महिला फुटबॉल टीम के साथ अपना प्रदर्शन कर रही हैं कोठी सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनके उ'जवल भविष्य की कामना की है और उनके ज'बे को देखते हुए

विश्वास जताया है कि निश्चित रूप से वह अपने दमदार खेल के बदौलत राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में सफल रहेंगी चेतना की इस नई चेतना से क्षेत्र के समस्त खिलाड़ी व जनता जनार्दन में खुशी की लहर दौड़ गई है प्रॉमिस त्रिपाठी बृजेश गर्ग सोनू उमेश सिंह पप्पू पंडित जगन्नाथ शर्मा जनपद सदस्य रीतू धीरेंद्र सिंह अजय सिंह बंटू तिलक राज सिंह गुड्डू सिंह सहित अन्य स्नेही जनो ने हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की है

अपने हकों के लिए किसान 28 अक्टूबर को कमिश्नर कार्यालय सहारनपुर चले :- भगत सिंह वर्मा

भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार अन्नदाता किसानों की भारी अनदेखी कर रही है -भगत सिंह वर्मा

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर । देवबंद, ग्राम बन्हेडा खास में एक बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार अन्नदाता किसानों की घोर उपेक्षा कर रही हैं। जिसके कारण किसानों पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला पा रही है। देश का अन्नदाता किसान एक-एक रुपए को मोहताज है। चीनी मिलें लागत मूल्य से भी कम 370 रुपए कुंतल समय से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं कर रही हैं। माननीय हाई कोर्ट व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज चीनी मिल गन्ना किसानों को नहीं कर रही है। जिसके लिए प्रदेश व केंद्र की सरकार सीधे-सीधे जिम्मेदार है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि इस वर्ष गन्ने की उत्पादन लागत 550 रुपए कुंतल है इसलिए प्रदेश की योगी सरकार गन्ने का लाभकारी मूल्य कम से कम 700 कुंतल तत्काल घोषित करें। एक वर्ष तक गन्ना उत्पादन करने वाले गन्ना किसान को उसकी लागत मूल्य भी नहीं मिलना शर्म की बात है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि महान कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गन्ने का लाभकारी मूल्य 825 कुंतल होना चाहिए। प्रदेश के गन्ना किसानों की मेहनत के बल पर उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिवर्ष एक्साइज ड्यूटी के रूप में 50 हजार करोड रुपए राजस्व वसूल रही है। इसके अलावा गन्ना चीनी बगास शिरा अल्कोहल आदि से हजारों उत्पाद बनते हैं ।जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष एक लाख करोड रुपए से अधिक जीएसटी व टैक्स प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी प्रदेश के गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल न दिलाना प्रदेश की गन्ना किसानों का घोर अपमान है। जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसानों के सभी कर्ज समाप्त कराने, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने, गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल कराने, चीनी मिलों द्वारा तत्काल गन्ना भुगतान व ब्याज दिलाने, ढुलाई किराया बंद कराने, कृषि यंत्रों खाद बीज दवा से जीएसटी समाप्त करने, किसानों को कृषि कार्य हेतु निःशुल्क बिजली दिलाने, स्मार्ट मीटर के नाम पर किसानों, मजदूरों व गरीबों का शोषण रोकने, एम एस पी को गारंटी कानून बनाने, 58 वर्ष से अधिक उम्र के किसान, मजदूर, गरीब सभी को 10000 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दिलाने, आवारा वह छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल को बचाने, पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण कराने जैसी समस्याओं को लेकर 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को तल्हेड़ी बुजुर्ग बस स्टैंड से सहारनपुर कमिश्नर कार्यालय पर जुलूस प्रदर्शन करते हुए महापंचायत की जाएगी। अपने हकों के लिए किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, दुकानदार, बुद्धिजीवी, पत्रकार सभी भारी संख्या में 28 अक्टूबर को कमिश्नर कार्यालय सहारनपुर पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता राव अफजल प्रधान ने की और संचालन भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश सचिव ऋषिपाल प्रधान गुर्जर ने किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष मांगेराम यादव, जिला उपाध्यक्ष वसीम जहीरपुर, जिला मंत्री महबूब हसन, हाजी बुद्धू हसन, राव मुस्तकीम, राव अनवर राव, फारूक राव, तनवीर राव, शाहिद अहमद, राव मुरसलीन, हाजी आबिद, हाजी साजिद, हाजी सुलेमान, राव खलील, राव दिलशाद आदि ने भाग लिया।

तौफीक जग्गी सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव नियुक्त

संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वह पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे - तौफीक जग्गी

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर । देवबंद, समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजपाल कश्यप ने तौफीक अहमद जग्गी को प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसैन ने तौफीक अहमद जग्गी को नियुक्त पत्र सौंपते हुए संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करने का आहवान किया। सपाइयों ने तौफीक अहमद जग्गी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान तौफीक अहमद ने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वह पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे।

रिजर्व फारेस्ट में पिकनिक, टल्ली ने तेंदुए को ललकारा

गुस्सैल तेंदुए ने 08 को किया घायल, बढ़ी सर्चिंग

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ । शहडोल, जिले में इस समय तेंदुए की दहशत का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जिसमे लोगो ने संभावना जताई है की जंगली जानवर अब आदमखोर हो गया, तो वही सोशल मीडिया में चर्चाओं में एक पक्ष का कहना था कि जंगल में जानवर नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा द्य हालांकि सोमवार सुबह से मंगलवार तक इंसानी और जंगली जानवरो के संघर्ष की खबरों से एक तरफ लोगो में दहशत का माहौल है, वही एहतियातन वन विभाग दलबल के साथ तेंदुए कि टेरेटरी पर नजर रखे हुए है, हादसे के सम्बन्ध में मिली जानकारी के मुताबिक वन परिक्षेत्र खेतौली के शोभा घाट में वारदात वाले दिन जमकर चल रही पार्टी के बीच जो बिना दावत के तेंदुआ आ गया, किसी ने सोचा भी नाही होगा लेकिन हुआ ऐसा की सामान्य जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली का दीदार हुआ तो एक पल के लिए तो सबने पार्टी को इंजॉय करते हुए अपने अपने मोबाइल निकले और वीडियो बनाना शुरू कर दिया द्य किसी ने डॉगी समझा तो डाट दिया तो किसी ने कहा आ आना

शांत जंगल में मचा कोहराम..वही चंद सेकंड में वीडियो बनाने वाले सख्स ने अ'छी फुटेज की खातिर जंगली जानवर वो भी तेंदुए को ललकारना शुरू कर दिया, सूत्र बताते है कि लगभग ललकारने वाले लोगो ने शराब पी रखी थी, और नशे में ही सही पर एक कांड तो हो गया जिसमे तेंदुआ पहले तो सब कुछ देखा तक़रीबन दस सेकंड शांत रहा और फिर एकदम से अटैक कर दिया जिसमे पुलिस विभाग में कार्यरत नितिन समदरिया निशाना बने, लेकिन वीडियो में साफा दिखाई दे रहा था कि तेंदुआ ने केवल हल्का पंजा मारा, और आगे निकल गया द्य नाही वो भूखा था नाही चोटिल जख्मी लोगो का शिकार किया द्य अगर भूखा होता तो जंगली जानवर अपना शिकार खींचकर जंगल ले जाते है द्य

अब तक आठ बने निशाना..दरअसल हमले में पुलिस महकमे में पदस्थ रेडियो ट्रांसमीटर सहायक उपनिरीक्षक नितिन समदरिया, आकाश कुशवाहा, नंदिनी सिह, जानकी बैगा, सजीवन सिंह, राकेश, समनु सहित एक अन्य व्यक्ति इस तेंदुए के हमले से घायल हो चुके है। तेंदुए के हमले से घायल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जहा महिला का इलाज जारी है।

बढ़ा दी गई गस्ती.. आठ लोगों को घायल करने तेंदुए के निगरानी के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने अब तीनों रेंज से 60 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। जो जंगलों में लगातार तेंदुए की निगरानी बनाए हुए हैं, जिसमें गोहपारु रेंज के रेंजर के साथ उनके कर्मचारी तैनात किए गए हैं, तो इधर जैतपुर क्षेत्र में जैतपुर रेंजर के साथ कई डिप्टी रेंजर एवं बीट गार्ड जंगलों में निगरानी बनाए हुए हैं। शहडोल वन परिक्षेत्र में वन परिक्षेत्रा अधिकारी के साथ उनकी टीम लगातार क्षेत्र में गस्ती कर तेंदुए पर निगरानी बनाए हुए है।

पिकनिक की आड़ में तस्करी..जानवरों के लगातार हो रहे शिकार और इंसान व जानवरों के बीच संघर्ष ने कई अहम प्रजातियों के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। अधिकतर जंगली जानवर लालच में मारा जाता रहा है। लोगों का अंधविश्वास है कि फला के सिंग में बहुत से औषधीय गुण होते हैं। शेर, चीते और हाथी खाल, दाँत इन सभी के अंगों को महंगी कीमत पर बेचने के लिए इनका शिकार किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर तेंदुए को लेते हैं। जंगल में तेंदुए को ललकारने के क्या मायने। मामले से सम्बंधित सूत्र बतलाते है की जानवरो को मार कर जादू टोना एवं तांत्रिक विधि अनुष्ठान इत्यादि में भारी डिमांड है और दिवाली में इसकी मांग बढ़ जाती है और शातिर लोगो ने इसी समय का फायदा उठाना चाहता है।

शीर्ष अफसर की अपील मामले में मिली जानकारी के बाद जिला मुख्यालय समेत वन परिक्षेत्र में मुनादी इत्यादि करवाने के साथ साथ लोगो को समूह में बैठाकर जंगली जानवरो को तंग ना किये जाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है, सीसीएफ शहडोल ने हुई बातचीत में बतलाया अनावश्यक लोगो को जंगलो में घूमने नहीं जाना चाहिए, और गये भी तो 20 अक्टूबर की तर्ज पर तो बिलकुल बर्ताव ना करे, जंगलो में शांति बनाये रखे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (Wildlife Protection Act v~|w in Hindi me) किसी भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी भी पौधे की प्रजाति (जीवित या मृत) को जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, एकत्र करने, बेचने या स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करता है।

किसने रौदा कायदा कानून.. हम आपको बता दे कि लुप्तप्राय प्रजाति जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जाता है। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिये खतरा हों अथवा वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हों, जिससे ठीक होना संभव नहीं है। अब जंगल आरक्षित भूमि में जाकर ललकारना क्या कहलाता है। डरा हुआ तेंदुआ अपने बचाव घूम रहा और लोगो को भी नुकसान पंहुचा रहा है। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार खतौली की वो शराब पार्टी है जिसमे साफ़ तौर पर देखा जा सकता है लाल रंग की थार और अभिषेक मिश्रा दिखाई दे रहा है, और बाकी ब्यक्ति भी साफ़ दिखाई दे रहे है, इन सभी लोगो तेंदुए को डराया जिससे अब तेंदुआ चारो ओर घूम रहा है। मामले में अपुस्ट जानकारी के मुताबिक लाल रंग की थार में राइफल लोड राखी रहती है और कई बार

इनका कहना है।

घटना के बारे में थोड़ा सुना हुआ है लोगो में सीक्रेंस की कमी है जंगली जानवर के इलाके में पिकनिक से बचना चाहिए, फिर उनको उकसाने से क्या फायदा हुआ, उल्टा नुकसान हुआ, वन विभाग को भी जागरूकता बतौर एक सख्त गाइड लाइन जारी करना करे, यहां बाघ तेंदुआ अथवा हांथी का मूवमेंट है, लोग सतर्क होंगे, जानवर और इंसानी संघर्ष काम होगा।

संतोष शुक्ला, सदस्य
मध्यप्रदेश वन्य प्राणी बोर्ड

आठ लोगों पर हमला करने वाले आदमखोर तेंदुए के रेस्क्यु के लिए भोपाल एवं बी टी आर टीम को पत्र लिखा है, जल्द ही टीम आकर इस आदमखोर तेंदुए का रेस्क्यु कर बांधवगढ़ ले जाएगी।

बादशाह रावत, एसडीओ, वन विभाग शहडोल

मामले में पिकनिक मानाने वाले लोगो की फुल गलती है, मैंने वायरल वीडियो देखा है, यह जंगली जानवर है आप उसके घर जाकर उसको ललकारते है उकसाते है तेज तेज आवाज़ करते है तेंदुआ डर गए और सभी की केवल जख्मी किया है, वरना उसके पंजे की ताक़त इतनी होती है की किसी आदमी के सर का कचूमर निकर दे, लेकिन किसी का शिकार नहीं हुआ और ता'जुब की बात है रहवासी इलाके में तेंदुआ नहीं घुसा आप उसके घर में घुस रहे है।

अजय कुमार पाण्डेय, सीसीएफ, शहडोल

इनके असलहा लेकर दहशतगर्दी फैलने के मामले में थाना कोतवाली में शिकायत भी दर्ज है, यह आदतन अपराधियों से आखिर कोई क्या उम्मीद कर सकता है वन विभाग को मामले में पड़ताल कर दोषियों को चिन्हित करते हुए कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कांकेर जिले की मासुलपानी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर मिला द्वितीय पुरस्कार

राजीव खरे । सिटी चीफ
(छत्तीसगढ़) कांकेर, जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासुलपानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय जलमंत्री सीआर पाटिल द्वारा ग्राम पंचायत मासुलपानी की सरपंच रमिया नेताम को पुरस्कृत किया। गौरतलब है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में मासुलपानी पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस ग्राम पंचायत में 161 जल शेड संरचनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 99 फार्म तालाब शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2023 के दौरान पंचायत द्वारा 39 नंबर ब्रशवुड, एक सामुदायिक तालाब डी-सिल्टिंग, 02 कुएं, 02 भूमिगत बांध, 03 गेबियन और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके चलते लोगों ने सिंचाई के लिए सतही जल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जल संरक्षण और इसके समुचित उपयोग की दिशा में इस नवाचार के लिए मासुलपानी ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और लोगों को सर्वोत्तम जल उपयोग प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार (एनडब्ल्युए) देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा 'जल समृद्ध भारत' के सरकार के विज़न को प्राप्त करने में किए गए अ'छे काम और प्रयासों पर केंद्रित है। ये पुरस्कार लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल और जिलाध्यक्ष नरेश गोयल पहुंचे देवबंद

व्यापारियों ने फूल मालाएं पहनाकर किया स्वागत

गौरव सिंघल । सिटी चीफ देवबंद (सहारनपुर), उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल और जिलाध्यक्ष नरेश गोयल का देवबंद आगमन पर व्यापारियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किया कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे रोड स्थित संगठन के उपाध्यक्ष परवेज खान के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी देश और सरकार की रीढ़ होता है। यदि व्यापारी परेशान होगा तो इसका असर देश में देखने को मिलेगा। उनका संगठन लगातार व्यापारियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहा है। कहीं भी व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तो उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। लेकिन व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर अध्यक्ष दीपक गर्ग ने कहा कि यदि कोई अधिकारी बिना वजह व्यापारियों को परेशान करता है तो उसको सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से आह्वान किया कि किसी भी स्तर पर उत्पीड़न बर्दाश्त न करें। इस मौके पर व्यापार श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलशाद चार्ली, सरफराज मलिक, मनमोहन गर्ग, सचिन गर्ग, मुस्तफा सलमानी, अजय जैन, लकी गोयल, सुनील कुमार, भारत भूषण, हसन, शाकिर आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिये युवा नेता आकाश शर्मा को बनाया उम्मीदवार

राजीव खरे । सिटी चीफ ।
(छत्तीसगढ़) रायपुर, कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए युवा नेता आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आकाश शर्मा छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इससे पहले सात साल तक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने उनके नाम पर सहमति जताई थी, जिसके बाद मंगलवार को उनके नाम पर अंतिम मुहर लगा दी गई। यह उपचुनाव 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। आकाश शर्मा का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सुनील सोनी से होगा। रायपुर दक्षिण सीट भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश शर्मा ने दावेदारी की थी, लेकिन तब कांग्रेस ने महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया था। इस बार आकाश शर्मा पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। आकाश शर्मा की दावेदारी को लेकर पार्टी के भीतर व्यापक सहमति बनी थी, हालांकि प्रारंभिक चर्चा में प्रमोद दुबे का नाम आगे था। रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद दो नामों का पैनल पार्टी हाईकमान को भेजा गया, जिसमें प्रमोद दुबे का नाम सबसे आगे था। लेकिन अंततः प्रमोद दुबे के नाम पर सहमति न बनने के कारण आकाश शर्मा को उम्मीदवार चुना गया। आकाश शर्मा की राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है। उन्होंने पहले भी विधानसभा चुनाव 2018 और 2023 में टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें उस समय मौका नहीं दिया। इस बार कांग्रेस ने

उनकी युवा नेतृत्व क्षमता पर विश्वास जताया और उन्हें रायपुर दक्षिण से टिकट दिया गया है। आकाश शर्मा छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और युवा पीढ़ी के बीच उनकी लोकप्रियता काफी है। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत एनएसयूआई से हुई थी, जहां उन्होंने सात साल तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सोमवार को आकाश शर्मा के नाम की घोषणा से पहले ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर पर इकट्ठा हो गए थे और सोशल मीडिया पर भी उनके लिए बधाई संदेश आने लगे थे। नाम घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आकाश शर्मा के नाम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है, जो इस चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदों को मजबूती प्रदान कर सकती है। प्रमोद दुबे, जो रायपुर नगर निगम में सभापति हैं और पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, ने कांग्रेस के टिकट की उम्मीद में नामांकन फॉर्म भी खरीदा था। हालांकि उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी उन्हें मौका देगी तो वे नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन अब आकाश शर्मा को टिकट दिए जाने के बाद प्रमोद दुबे और अन्य दावेदारों ने पार्टी के निर्णय का सम्मान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी यह स्पष्ट किया कि सभी दावेदारों से चर्चा हो चुकी है और उन्होंने वादा किया है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी, सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और वे 34 साल पुराना इतिहास बदलने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण की जनता को यह बताना जरूरी है कि सुनील सोनी, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सांसद और महापौर होने के बावजूद क्षेत्र के लिए क्या खास उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। उन्होंने सुनील सोनी को सबसे निष्क्रिय सांसद करार दिया और कहा कि जनता के बीच जाकर उनकी उपलब्धियों को बताया जाना चाहिए। बीजेपी की ओर से रायपुर दक्षिण सीट के लिए सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया गया है। बृजमोहन अग्रवाल, जो इस सीट से विधायक थे और अब सांसद बन चुके हैं, ने कांग्रेस की टिकट घोषणा पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित करने में काफी देरी कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में चार गुटों के झगड़े के बाद प्रत्याशी का चयन हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी तंज कसा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, जिसका रायपुर से कोई विशेष संबंध नहीं है। रायपुर दक्षिण सीट पर 2023 तक हुए चार चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार हर बार बड़े अंतर से हारे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के कन्हैया अग्रवाल सबसे कम वोटों के अंतर से हारने वाले प्रत्याशी थे, जब बृजमोहन अग्रवाल की लीड महज 17,496 वोटों की थी। हालांकि, 2023 के चुनाव में बृजमोहन ने कांग्रेस के डॉ. महंत रामसुंदर दास को 67,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया था। अब देखना यह है कि इस उपचुनाव में आकाश शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बनाती है और क्या वह पिछले 34 साल का इतिहास बदलकर इस सीट पर जीत हासिल कर पाती है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की हुई बैठक

मुख्यमंत्री बोले -आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार

राजीव खरे । सिटी चीफ
(छत्तीसगढ़) रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशुपर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। प्राधिकरण के सदस्यगणों तथा प्रमुख विभागों के सचिवों के उपस्थित में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अंतर्गत् स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की और निर्देशित किया कि अप्रारंभ कार्यो को निरस्त कर प्रगतिरत् कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से वन-टू-वन चर्चा कर उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की। उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने विधायक रेणुका सिंह की मांग पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की। प्राधिकरण की बैठक संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय से ही प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए प्राधिकरण का गठन कर संसाधन उपलब्ध कराए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पांच प्राधिकरण है। हमारी सरकार चाहती है कि बस्तर से लेकर सरगुजा क्षेत्र तक का विकास हो। इसके लिए बजट में राशि नहीं होने पर प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। भारत सरकार और रा'य सरकार चाहती है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गो का विकास हो। प्राधिकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में संसाधन की व्यवस्था कर विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य और आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु बजट का प्रावधान किया है। उनकी इन योजनाओं से रा'य के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यो को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने बजट में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए फोकस किया है। हमारी सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग क्षेत्र के विकास के लिए वचनवद्ध होकर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के मयाली में प्राधिकरण की बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारी की सरहाना की और कहा कि जशपुर जिले में खनिज संसाधनों का भण्डार होने के साथ ही वन एवं वनोपज की उपलब्धता है। यहॉ के वनोपज, महत्वपूर्ण उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर ग्रामीणों एवं किसानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण की बैठक अपने गृह जिले तथा मयाली में करने के पीछे यहॉ के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहते हुए राजधानी रायपुर से बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि वे यहॉ के उत्पादों को देखे, इसका उपयोग करे और इन्हें बढ़ावा देने के साथ ही जशपुर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा बताए गए समस्याओं को

निराकरण करने की बात कही। उन्होंने लुण्ड्रा-बतौली क्षेत्र में गन्ना खरीदी केन्द्र को प्रारंभ करने की मांग का परीक्षण करने, विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने की दिशा में कार्य करने, हाथी से जनहानि रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने, क्षति की राशि को बढ़ाने की दिशा में विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने एकल बत्ती कनेक्शन सहित अन्य लोगों को अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायत पर ऊर्जा सचिव रोहित यादव को निर्देशित किया कि बिजली बिल संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण कराए। उन्होंने खाद्य विभाग के सचिव को जशपुर जिले के कुछ स्थानों पर राशन की कमी संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुनकुरी में जल संसाधन संभाग के संभागीय कार्यालय का लोकार्पण रिमोट का बंटन दबाकर किया। बैठक में उपस्थित उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्र का विकास हमारी सरकार की सर्वो'च प्राथमिकता का विषय है। प्राधिकरण अंतर्गत् आज की बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की विकास की प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्राधिकरण के माध्यम से सरगुजा संभाग के लोगों की जीवन में परिवर्तन लाकर उनके जीवन को सुलभ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि उन्होंने अपने अधीनस्थ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगरी प्रशासन विकास विभाग बैठक लेकर महत्वपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। शहर को स्व'छ एवं सुंदर बनाने एवं अन्य कार्यो के लिए राशि जारी की है। पीडब्ल्यूडी अंतर्गत् सड़कों के मरम्मत के आदेश दिए गए हैं और तेज गति से कार्य करते हुए नवम्बर माह तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत् कार्यो की समीक्षा कर घर-घर नल और जल पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस योजना में दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ''हमने बनाया है हम ही संवारेगें'' की दिशा में कार्य कर रही है। प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने जशपुर जिले में पर्यटन की अपार संभावना होने की बात कहते हुए प्राधिकरण की बैठक मयाली में होना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से उत्तर क्षेत्र सरगुजा संभाग से विकास कार्यो की शुरूआत छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाएगा।? कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्राधिकरण का बैठक मयाली में आयोजित करने का उददेश्य इस क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर निराकृत करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि गांव को ईकाई बनाकर विकास कार्यो की शुरूआत कर प्रदेश का विकास किया जा सकता है। उन्होंने सरगुजा संभाग के महत्वपूर्ण उत्पादों की जानकारी देते हुए इसे बढ़ावा देने पर जोर दिया। मंत्री श्री नेताम ने प्राधिकरण के सदस्यों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के आश्रम-छात्रावासों की समस्याओं से भी अवगत करावें, ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। बैठक में उद्योग, वाणि'य एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्राधिकरण की पहली बैठक आयोजित करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि बैठक के माध्यम से सरगुजा संभाग में महत्वपूर्ण कार्य आसानी से हो पाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद रायगढ़ राधेश्याम राठिया, सांसद सरगुजा चिन्तामणि महाराज, विधायक जशपुर रायमुनी भगत, विधायक लुण्ड्रा प्रमोद मिंज, विधायक प्रतापपुर शकुंतला सिंह पोर्त, विधायक अंबिकापुर राजेश अग्रवाल, विधायक भरतपुर सोहत रेणुका सिंह, भैया लाल राजवाड़े तथा जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं की जानकारी देकर निराकरण की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों की समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

इजराइल से तनातनी के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मोदी की हुई मुलाकात

जानिए किन बातों पर हुई चर्चा

कजान: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। ईरान और इजराइल के मध्य बढ़ते तनाव के बीच पेजेशकियन ने पश्चिम एशिया में शांति की आवश्यकता पर बल दिया तथा सभी पक्षों के साथ भारत के अछे संबंधों के कारण संघर्ष को कम करने में उसकी भूमिका पर जोर दिया। जुलाई में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बने पेजेशकियन और मोदी के बीच यह पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) सहित प्रमुख

क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं में 'एक्स पर लिखा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ बहुत अछी बैठक हुई। हमने अपने देशों के बीच संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की। हमने भविष्य के क्षेत्रों में संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने यहां प्रेसवार्ता में बताया कि मोदी और पेजेशकियन के बीच ''सार्थक चर्चा हुई।

मिसरी ने कहा, ''दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत के आह्वान को दोहराया। उन्होंने तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति पेजेशकियन ने क्षेत्र में शांति एवं सद्भाव की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भारत सभी संबंधित पक्षों के साथ अपने अछे संबंधों के कारण संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेशकियन को उनकी हालिया चुनावी जीत पर बधाई दी और ईरान के साथ सदियों पुराने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहरायी। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने ब्रिक्स परिवार में ईरान का स्वागत भी किया। मिसरी ने कहा, चर्चा में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मिसरी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा में अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठा। उन्होंने कहा, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पेजेशकियन को शीघ्र भारत आने का निमंत्रण दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति पेजेशकियन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया।

ताबूत में दफनाने जा रहे थे मां-बाप

अचानक बच्ची ने पकड़ ली उंगली

डॉक्टर ने कर दिया था मृत घोषित

नेशनल डेस्क. एक दिल दहला देने वाली घटना में, एक आठ महीने की बच्ची को उसके परिवार ने दफनाने की तैयारी कर ली थी, जब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इस बच्ची की मौत की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले उसे फिर से अस्पताल ले जाना पड़ा।

घटना का विवरण

ब्राजील में हुई इस घटना में बच्ची, जिसका नाम कियारा बताया जा रहा है, को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। उसके माता-पिता अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, जब उन्होंने उसे नए कपड़े पहनाए। इसी दौरान, एक फार्मासिस्ट ने देखा कि बच्ची की सांसें चल रही हैं। जब

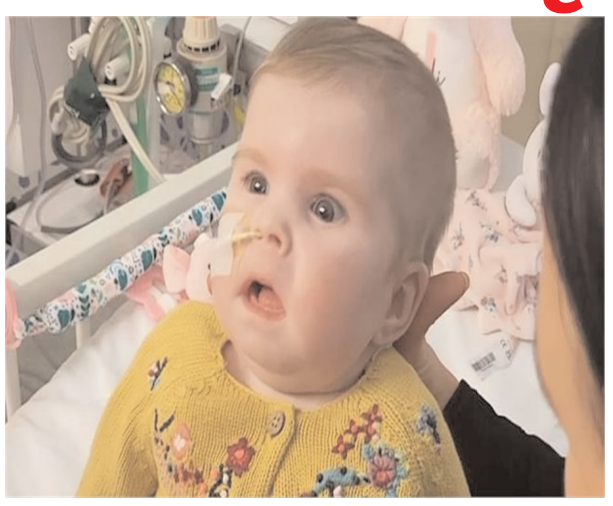

एक शख्स ने उसकी उंगलियों को छुआ, तो बच्ची ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद, आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया। बच्ची को ताबूत से निकालकर फौरन अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान, पैरामेडिक्स ने पाया कि कियारा की नब्ज चल रही थी और उसे गंभीर देखभाल की जरूरत थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करने के 16 घंटे बाद फिर से अस्पताल लाने पर उसकी जीवित होने की पुष्टि की।

अस्पताल की जांच और माफी

बच्ची को अस्पताल वापस लाने पर उसे एक बार फिर मृत घोषित कर दिया गया।

इस मामले की जांच के बाद, ब्राजील के विशेषज्ञ वैज्ञानिक पुलिस ने यह पाया कि अस्पताल ने बच्ची की मृत्यु की घोषणा उसके वास्तविक निधन से पहले कर दी थी। अस्पताल ने कियारा के माता-पिता से माफी मांगी और मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया।

ग्लोबल साउथ को भारत के नेतृत्व पर भरोसा

नई दिल्ली में बोले भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे

नई दिल्ली: भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे का कहना है कि विश्व के सवा सौ से अधिक विकासशील देशों के समूह ग्लोबल साउथ को भारत के नेतृत्व पर भरोसा है और वह मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त करवा सकते हैं।

भूटानी प्रधानमंत्री ने सोमवार को यहां एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में यह बात कही। उन्होंने कहा,''भारत की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी है, इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। यह तीस खरब (तीन ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। अगर कोविड नहीं होता तो इसे पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करना चाहिए था। उन्होंने कहा,''भारत में लगभग साढ़े तीन करोड़ प्रवासी लोग हैं। हर पैमाने पर, यह भारत की शताब्दी है, लेकिन आप नेतृत्व के एक पैमाने पर खड़े हैं, और

उस नेतृत्व में सबका विश्वास है। न केवल भारतीय भारत के नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक दक्षिण भारत के नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है।

तोब्गे ने कहा कि ग्लोबल साउथ (दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील, कम विकसित और अविकसित देश) नेतृत्व के लिए भारत की तरफ देखता है और अगर कोई ऐसा देश है, जो आज के दौर की समस्याओं को सुलझा सकता है, तो वह भारत है। उन्होंने कहा, चाहे आर्थिक समस्याएं ही क्यों न हों, दुनिया भारत को एक बाजार के रूप में देखती है...कोविड-19 महामारी के दौरान... दुनिया ने टीकों और दवाओं केलिए भारत की ओर देखा, यहां तक ??कि रूस और यूक्रेन ने भी, मुझे यकीन है कि अगर कोई व्यक्ति इसे सुलझा सकता है, तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं।

टूडो की घटिया राजनीति की भेंट चढ़ रहा कनाडा

खालिस्तान की आग में घी डाल रहा पाकिस्तान

इण्टरनेशनल डेस्क। हाल के महीनों में भारत और कनाडा के बीच एक राजनयिक विवाद उभरा है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय कर्मचारियों पर कनाडा में जासूसी और हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। यह कहानी कनाडाई सरकार और पश्चिमी मीडिया में काफी सुर्खियों में है। लेकिन इस बीच, पाकिस्तान की खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन में भूमिका पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो भारत को विभाजित करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। ट्रूडो का ध्यान भारत के कथित कार्यों पर केंद्रित करना, असली समस्या से मुंह मोड़ने जैसा है, जिसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। पत्रकार फ्रांसेस्का मरीनो ने यह बताया है कि खालिस्तानी अलगाववादी, जो स्वतंत्र पंजाब की मांग करते हैं, कभी भी लाहौर, जो इतिहास में पंजाब की राजधानी रही है, को निशाना नहीं बनाते। यह संयोग नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ लंबे समय से इस आंदोलन को समर्थन दे रही हैं।

कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने भी पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार किया है। सीएसआईएस अधिकारी वनेसा लॉयड ने बताया कि पाकिस्तान का समर्थन खालिस्तानी उग्रवाद से सीधे संबंधित है। इसके बावजूद, कनाडा पाकिस्तान के हस्तक्षेप को कम करके आंक रहा है और भारतीय कर्मचारियों की गतिविधियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। खालिस्तानी आंदोलन को एक सच्चे सिख आत्म-नियमन की आवाज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक प्रभावी प्रयास के रूप में देखा

जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य भारत की स्थिरता को खतरे में डालना है। जबकि ट्रूडो की सरकार भारतीय कर्मचारियों को बदनाम कर रही है, यह पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज कर रही है, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।

ट्रूडो की राजनीति पर सवाल उठते हैं। कनाडा ने भारतीय कर्मचारियों की गतिविधियों को ज्यादा महत्व क्यों दिया है, जबकि पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज किया है? कनाडाई मीडिया भी इस नफरत को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें भारत को खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है। कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसी, विशेषकर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस , भारतीय कर्मचारियों पर आलोचना कर रही है। हाल ही में इसके एक बयान में कहा गया है कि भारतीय कर्मचारी खालिस्तानी उग्रवादियों की गतिविधियों की जानकारी जुटा रहे हैं। यह आरोप न केवल असंगत है, बल्कि बेहद स्वार्थी भी है। इस सब से स्पष्ट है कि खालिस्तान आंदोलन सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है; यह पंजाब क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता रखता है। अगर कनाडा पाकिस्तान की भूमिका पर से ध्यान हटा रहा है, तो यह अपने देश और वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजनीतिक इरादों के कारण Trudeau का यह प्रयास खालिस्तान उग्रवाद पर सही चर्चा को रोकने का काम कर रहा है, जो मोटे तौर पर कनाडा और विश्व के लिए खतरा बन सकता है।

भारत किसी भी अन्य देश से अधिक हकदार

UNSC में भारत की स्थाई सदस्यता को लेकर बोला जर्मनी

नई दिल्ली: भारत और भूटान में जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने सोमवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाने के लिए भारत किसी भी अन्य देश से अधिक हकदार है। डॉ. एकरमैन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत समीकरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे वैश्विक स्तर पर मुख्य अभिनेताओं में से एक बनना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत के बिना जी-20 घोषणापत्र संभव नहीं होता। रूस और पश्चिम के बावजूद, भारत ने संतोषजनक परिणाम हासिल किया, जो दर्शाता है कि उसका कितना महत्व है। भू-राजनीतिक व्यवधान- उभरती हुई शक्तियां बनाम मौजूदा शक्तियां शीर्षक वाले सत्र में, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पश्चिम एशिया का मामला भी उठाया, जहां गैर-राय अभिनेता राय अभिनेताओं को चुनौती दे रहे हैं। इजरायल-हमास-हिजबुल्लाह संघर्ष का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि बदलती हुई दोष रेखाओं के जबरदस्त नतीजे होने वाले हैं। द एशिया ग्रुप के पार्टनर अशोक मलिक ने कहा कि भारत के आर्थिक और राजनीतिक हितों, दुनिया भर में प्रवासियों और ऊर्जा की कीमतों जैसे कारकों को देखते हुए, पश्चिम एशिया भी नई दिल्ली की समस्या बन गया है।

इस पर अकबरुद्दीन ने कहा, चुनौती वैश्विक व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की होगी। चुनौतियां सिर्फ राय से ही नहीं आएंगी, बल्कि जलवायु, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष से भी आएंगी। इनका समाधान केवल साझेदारी के माध्यम से ही निकलेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या पुराने वैश्विक शक्ति समीकरणों के बदलने की जरूरत है, एकरमन ने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा, यूरोप और जर्मनी खासतौर पर मानते हैं कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगे आने होगा। भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुख्य शक्तियों में शुमार होना होगा और यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। एकरमैन ने कहा कि जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान तथाकथित जी-4 है और हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षित परिषद की स्थाई सदस्यता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत वहां स्थाई सीट का किसी अन्य देश से यादा हकदार है। और, हम यह भी आशा करते हैं कि इन अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों में सुधार होने जा रहा है। वहीं, नोबरेगा ने कहा, ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण पर ब्राजील ग्लोबल साउथ और पश्चिम के बीच पुल बनाने में भारत का पारंपरिक भागीदार बनने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा, भारत में यह नेतृत्व संभालने की सभी योग्यताएं हैं।

ताजा सर्वेक्षण में नाटकीय मोड़ ! कमला हैरिस को झटका, पहली बार ट्रंप निकले आगे

वाशिंगटन: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में महज कुछ हफ्ते रह गए हैं। 5 नवंबर को होने वाले इस चुनाव से पहले ताजा सर्वेक्षण में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को बड़ा झटका लगा है। पहली बार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वेक्षण में हैरिस को पीछे छोड़ दिया है। डिसिजन डेस्क हिल के अनुसार, ट्रंप अब हैरिस से चार प्रतिशत आगे हैं, जिसमें ट्रंप की जीत की संभावना 52 प्रतिशत और हैरिस की 48 प्रतिशत बताई जा रही है। चुनाव से पहले दोनों प्रत्याशी जोर-शोर से अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि ट्रंप को कुछ महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स में बढ़त मिलती दिख रही है, जिनमें विस्कॉन्सिन और मिशिगन शामिल हैं। इसके अलावा, एरिजोना, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना में भी उनकी बढ़त बनी हुई है। हालांकि, डिसिजन डेस्क ने चेतावनी दी है कि चुनाव परिणाम अभी भी अनिश्चित हैं, क्योंकि चुनावी परिणाम स्विंग स्टेट्स पर निर्भर करते हैं। इन सात राज्यों—नेवादा, एरिजोना, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, पेनसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन—का परिणाम चुनाव की निष्पक्षता को निर्धारित कर सकता है। कमला हैरिस के लिए यह लेकर चिंता का विषय है कि चुनावी सर्वेक्षण में ट्रंप के प्रति बढ़ता समर्थन उनके लिए चुनौती पेश कर रहा है। इस बीच, वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी नेता स्वदेश चटर्जी ने बताया कि अमेरिकी भारतीय समुदाय हैरिस को मतदान करने में संकोच कर रहा है, उनके कार्यकालों के दौरान समुदाय से पर्याप्त रूप से जुड़ाव न करने के कारण।

चटर्जी ने 'इंडियन अमेरिकन्स फॉर हैरिस' नामक समूह की स्थापना की है, जो उपराष्ट्रपति के लिए न केवल कैलिफोर्निया में, बल्कि अन्य राज्यों में भी अभियान चला रहा है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय अमेरिकी मतदाता अभी भी हैरिस को समर्थन देने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते।इस चुनावी दौड़ में इतनी नाटकीय परिवर्तन के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हैरिस अपनी स्थिति को पुन: मजबूत कर पाती हैं या ट्रंप चुनावी परिदृश्य में अपनी बढ़त को बनाए रखेंगे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569